● वर्ष-4
● अंक-64
रायपुर, बुधवार 23 अक्टूबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» वेडिंग गिफ्ट जा रही है खरीदने...

झारखंड में बनेगी एनडीए सरकारः चिराग पासवान

पटना। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को भरोसा जताया कि एनडीए झारखंड में एक मजबूत सरकार बनाएगी, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हरियाणा के बाद अपनी अगली बड़ी हार की ओर बढ़ती दिख रही है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख ने यह भी कहा कि वह राज्य में भाजपा की एक सीट की

पेशकश से संतुष्ट हैं और उन्होंने उन अटकलों को खारिज कर दिया कि इस सौदे से उन्हें अपमानित महसूस हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को भरोसा जताया कि झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' हरियाणा के बाद अगली बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा)- रामविलास के प्रमुख चिराग ने यह भी कहा कि वह झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा उनकी पार्टी को एक सीट की पेशकश किये जाने से 'संतुष्ट' हैं। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि इस सीट समझौते से उन्हें अपमानित महसूस हुआ है।

पासवान ने संवाददाताओं से कहा, बहुत से लोग हैं, जो मेरे और प्रधानमंत्री के बीच दरार डालना चाहते हैं। वे कभी सफल नहीं होंगे। मैं यह बताना देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी न केवल खुश है बल्कि पूरी तरह से संतुष्ट है कि भाजपा ने झारखंड में भी हमें उचित सम्मान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 24 अक्टूबर को उनकी पार्टी के उम्मीदवार जनार्दन पासवान नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और इस दौरान वह खुद झारखंड का दौरा करेंगे।

पासवान ने कहा, अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के अलावा पार्टी अपने सहयोगियों को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए रणनीति तैयार करेगी। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में भाजपा 68 सीट पर और उसके सहयोगी दल ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 10, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड दो और लोजपा एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। पासवान ने कहा, हमें विश्वास है कि राजग झारखंड में मजबूत सरकार बनाएगी और कांग्रेस नीत 'इंडिया' गठबंधन हरियाणा के बाद अपनी अगली बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है।

यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए भारत हरसंभव सहयोग देने को तैयार-मोदी

मोदी - पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक

कज़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की और उनसे कहा कि वे यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र, शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं और उन्होंने कहा, भारत हमेशा शांति लाने में मदद करने के लिए तैयार है। मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा, मैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर लगातार आपके संपर्क में रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र स्थापना का पूरा समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयासों में मानवता को प्राथमिकता दी गई है। भारत आने वाले समय में हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले तीन महीनों में रूस की उनकी लगातार यात्राओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। उन्होंने बैठक के दौरान कहा, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कज़ान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिलना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कज़ान में भारत के नए वाणिज्य दूतावास के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे।

प्रधानमंत्री ने पुतिन से कहा यूक्रेन विवाद को सुलझाने के लिए भारत हरसंभव सहयोग देने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कज़ान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर रूसी राष्ट्रपति

व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हरसंभव सहयोग देने की भारत की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के विषय पर मैं लगातार आपके संपर्क में रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र स्थापना का पूरा समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयासों में मानवता को प्राथमिकता दी जाती है। भारत आने वाले समय में हरसंभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले तीन महीनों में रूस की अपनी दो यात्राओं को भी याद करते हुए कहा कि वे हमारे घनिष्ठ समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाती हैं। पुतिन के अलावा प्रधानमंत्री के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने और अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की संभावना है। यह शिखर सम्मेलन रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व संकट सहित चल रही वैश्विक अशांति के मद्देनजर हो रहा है।

उन्होंने कहा, भारत का हमेशा से यह मानना रहा है कि संबंधित पक्षों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष का समाधान खोजने की आवश्यकता है। पिछले महीने पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र माना और रूस-यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की तलाश में भारत के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। यह तब हुआ जब रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया। पुतिन की यह स्वीकृति प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उन्हें फोन करने और दो साल से चल रहे युद्ध के शीघ्र समाधान का आग्रह करने के दो महीने बाद आई है।

मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक आज

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर उपजा तनाव के अब खत्म होने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए, क्योंकि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच करीब पांच साल बाद द्विपक्षीय बैठक कल होने जा रही हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने पीएम मोदी की आज की बैठकों को लेकर जानकारी साझा करने के दौरान बताया कि पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कल रूस के कज़ान शहर में द्विपक्षीय बैठक होगी। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि कल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। हालांकि उन्होंने इस दौरान इस द्विपक्षीय बैठक को लेकर और कोई अन्य जानकारी नहीं साझा की है। वहीं भारत-चीन के बीच एलएसी पर सीमा पर गश्त को लेकर सहमति बनने पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि, चर्चा के तहत लंबित क्षेत्रों में, गश्त और चराई गतिविधियां, जहां भी लागू हो, 2020 की स्थिति पर वापस आ जाएंगी।

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर समाधान की बात पर चीन ने लगाई मुहर

भरोसा करने में लगेगा समय

नई दिल्ली। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटने की भारत की इच्छा व्यक्त की। यह भारत-चीन सीमा गश्त समझौते के बारे में सेना प्रमुख का पहला बयान है। व्यापक बातचीत के बाद, भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में 2020 पर गलवान झड़प से पहले की गश्त व्यवस्था पर लौटने के लिए आम सहमति पर पहुँच गए हैं, जो 2020 से पहले प्रभावी थी। उनकी टिप्पणी भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री द्वारा सोमवार (21 अक्टूबर) को घोषणा किए जाने के एक दिन बाद आई है कि दोनों पक्ष एलएसी के साथ क्षेत्रों में गश्त करने की व्यवस्था पर सहमत हो गए हैं। इन क्षेत्रों में देपसांग मैदान और डेमचोक शामिल हैं, जो टकराव के बिंदु हैं, जिनका समाधान नहीं हो सका है। समझौते में देपसांग और डेमचोक क्षेत्र शामिल हैं। सेना प्रमुख ने सेवानिवृत्त सेना जनरल सतीश दुआ की पुस्तक ए जनरल रिमिनिसेस - लाइफ अंडर फायर इन कश्मीर के विमोचन के दौरान कहा, हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस जाना चाहते हैं। इसके बाद हम एलएसी के विघटन, डी-एस्केलेशन और सामान्य प्रबंधन पर विचार करेंगे... अप्रैल 2020 से हमारा यही रुख रहा है। उन्होंने कहा, फिलहाल हम विश्वास बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तब होगा जब हम एक-दूसरे को देख पाएंगे और हम एक-दूसरे को यह समझाने और आश्वस्त करने में सक्षम होंगे कि हम बनाए गए बफर जोन में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि पूर्वी लद्दाख में विवादास्पद विघटन प्रक्रिया पूरी हो गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में शामिल होने से पूर्व विभिन्न विभागीय स्टॉल्स का अवलोकन किया उन्होंने इस मौके पर महिला समूहों द्वारा निर्मित महुआ के विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं अन्य उत्पादों की सराहना की।

प्रमुख समाचार

ईरान के राष्ट्रपति से मोदी ने की मुलाकात

कज़ान। रूस के कज़ान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं से ब्रिक्स सम्मेलन से अलग एक मुलाकात में पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने पर जोर दिया। साथ ही ईरान और इस्राइल के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए भारत की भूमिका को बात की। इसके अलावा दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से पीएम मोदी की यह पहली मुलाकात थी। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच सार्थक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ते संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा और नुकसान की रोकथाम के लिए भारत के आह्वान को दोहराया।

उपचुनावः दक्षिण रायपुर से आकाश शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से मंगलवार को कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस ने युवा नेता आकाश शर्मा को टिकट दिया है। आकाश शर्मा का मुकाबला बीजेपी के सुनील सोनी से है। सुनील सोनी रायपुर के मेयर रह चुके हैं और रायपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। आकाश पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वह अभी छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इससे पहले वह एनएसयूआई में के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के प्रभाववाली सीट सीट पर 35 साल के युवा पर दांव लगाकर लड़ाई को रोचक कर दिया है। 2014 से 2020 तक आकाश शर्मा एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2018 में वह एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव बने। बताया जा रहा है कि आकाश शर्मा के नाम पर पार्टी के सभी सीनियर नेता सहमत थे। आकाश शर्मा के उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि उनके नाम पर भूपेश बघेल, चरणदास महंत, दीपक बैज और टीएस सिंहदेव भी सहमत थे।

मोहन भागवत से मिले योगी आदित्यनाथ

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में नौ सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच सर संघ चालक मोहन भागवत मथुरा के दौरे पर हैं। मथुरा में ही आरएसएस प्रमुख से योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। यह मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ आगरा के लिए रवाना हो गए। अब इन दोनों ही नेताओं के बीच मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर बैठक को लेकर अभी कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जन्मस्थली फरह से सटे गांव में दोनों की मुलाकात के लिए 45 मिनट का समय निर्धारित था। लेकिन मुलाकात तय वक्त से ज्यादा करीब 90 मिनट तक चली। दरअसल, यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। राज्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन ने कमाल कर दिखाया है। राज्य की 80 में से 43 सीटों पर गठबंधन ने जीत दर्ज की है। वहीं बीते एक दशक में यूपी में यह बीजेपी की सबसे बड़ी हार है।

2024 में 7% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था

नई दिल्ली। भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2023 के 8.2 प्रतिशत से घटकर 2024 में सात प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है। 2025 में यह और घटकर 6.5 प्रतिशत रह जाएगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मंगलवार को यह अनुमान जताया। आईएमएफ ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से बनी दबी मांग खत्म हो गई है, क्योंकि अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता के साथ फिर से आकार ले रही है। आईएमएफ के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई काफी हद तक जीत ली गई है, हालांकि कुछ देशों में कीमतों का दबाव अब भी बना हुआ है। प्रमुख मुद्रास्फीति 2022 की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 9.4 प्रतिशत की ऊंचाई पर पहुंच गई थी, जिसके बाद यह 2025 के अंत तक गिरकर 3.5 प्रतिशत तक आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो यह 2000 और 2019 के बीच 3.6 प्रतिशत के औसत स्तर से भी कम होगा। आईएमएफ ने वाशिंगटन में जारी वार्षिक विश्व आर्थिक परिदृश्य में अनुमान लगाया कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2024 और 2025 में 3.2 प्रतिशत पर स्थिर रहेगी। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे-ओलिवियर गौरींचस के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति को काबू में करने के

सेबी की अध्यक्ष को सरकार से मिली क्लीन चिट!

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच के खिलाफ आरोपों की जांच में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया, सरकारी सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया, साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपना कार्यकाल पूरा करेंगी जो फरवरी 2025 में समाप्त हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च और कांग्रेस पार्टी द्वारा सेबी प्रमुख के खिलाफ हितों के टकराव और वित्तीय कदाचार के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद जांच जरूरी हो गई थी। हितों के टकराव और वित्तीय कदाचार के आरोपों को लेकर बुच की जांच की गई। विवाद तब शुरू हुआ जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने हितों के टकराव और वित्तीय कदाचार के आरोपों पर सेबी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच की चुप्पी पर सवाल उठाया। हिंडनबर्ग ने सुझाव दिया कि बुच के अडानी समूह से अघोषित वित्तीय संबंध हो सकते हैं, जिसकी भी जांच की जा रही है। आरोपों के जवाब में, माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए दावे निराधार और बिना किसी योग्यता के हैं।

उत्तर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग, दक्षिणी में बढ़ाने का आह्वान

देश में एक ओर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाये जाने की मांग हो रही है तो दूसरी ओर दक्षिण भारत के दो प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी जनता को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की बुजुर्ग होती आबादी को देखते हुए पिछले हफ्ते कहा था कि लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए कानून लाने की योजना भी बना रही है। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक पुराने आशीर्वाद का जिक्र करते हुए लोगों को 16 बच्चे पैदा करने की सलाह और शुभकामना दे डाली। दरअसल दोनों मुख्यमंत्री यह सलाह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जल्द ही देश में संसदीय सीटों का नये सिरे से परिसीमन होना है। इस परिसीमन के मुताबिक दस लाख लोगों की आबादी पर एक सांसद होगा। दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के मामले में तो बेहतरीन प्रदर्शन कर दिया लेकिन अब इसकी वजह से वहां प्रजनन दर कम हो गयी है जिससे उन्हें डर है कि यदि आबादी के लिहाज से संसदीय सीटों का निर्धारण हुआ तो देश की राष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह उत्तर भारत केंद्रित हो जायेगी।

हम आपको यह भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) द्वारा तैयार इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में बुजुर्गों की आबादी अधिक है। रिपोर्ट कहती है कि 2021 और 2036 के बीच इन राज्यों में बुजुर्गों की दर में बहुत अधिक तेजी से वृद्धि होगी। माना जा रहा है कि केरल की जनसंख्या में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 2021 की 16.5% से बढ़कर 2036 में 22.8% हो जाएगी। तमिलनाडु में 13.7% से बढ़कर 2036 में 20.8% हो जाएगी, आंध्र प्रदेश में 2021 के 12.3% से बढ़कर 2036 में 19% हो जाएगी, कर्नाटक में बुजुर्गों की आबादी 11.5% से बढ़कर 2036 में 17.2% हो जाएगी और तेलंगाना में 2021 के 11% से बढ़कर 2036 में 17.1% हो जाएगी।

मोटे तौर पर देखें तो 15 साल की इस अवधि में जनसंख्या में बुजुर्गों का अनुपात दक्षिण में 6-7% बढ़ जाएगा जबकि उत्तर में यह लगभग 3-4% होगा। वैसे एक तथ्य गौर करने लायक है कि अधिकांश दक्षिण भारतीय राज्य दुनिया के विकसित देशों की प्रजनन स्तर तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 2016-19 के लिए कराए किए गए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में जीवन प्रत्याशा 69.1 वर्ष, केरल में 71.9 वर्ष और तमिलनाडु में 71.4 वर्ष थी। केवल कर्नाटक की जीवन प्रत्याशा दर राष्ट्रीय औसत से थोड़ी कम यानि 67.9 थी। इसके

अलावा, एक समस्या यह है कि भारत ने अपनी प्रजनन दर बहुत तेजी से कम की है। हम आपको बता दें कि प्रति महिला छह बच्चों से घटकर दो या एक बच्चे पर आने में फ्रांस को 285 साल लगे, इंग्लैंड को 225 साल लगे लेकिन भारत को इस काम में सिर्फ 45 साल लगे। चीन ने हालांकि इससे भी कम समय में जनसंख्या को नियंत्रित किया लेकिन वहां ऐसा अत्यंत कठोर और दंडात्मक प्रावधानों के चलते संभव हो सका। इसके अलावा, दक्षिणी राज्यों की चिंता का बड़ा कारण जल्द ही होने वाला लोकसभा सीटों का परिसीमन भी है। यह कार्य जनगणना के तुरंत बाद होगा। हम आपको बता दें कि देश में वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएँ जनसंख्या के अनुसार तय की जाती हैं।

यदि जन्म दर स्थिर रहती है तो आंध्र प्रदेश में संसद सीटों की संख्या 25 से घटकर 20, कर्नाटक में 28 से 26, केरल में 20 से 14, तमिलनाडु में 39 से 30 और तेलंगाना में 17 से 15 तक हो जाने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर, उत्तर के राज्यों की जनसंख्या अधिक होने से उनके निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे उन्हें संसद में बड़ी आवाज मिलेगी। इसके अलावा यदि संसद की सीटें बढ़ाने का फैसला होता है तो भी उत्तरी राज्यों को ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि दक्षिण में जनसंख्या अनुपात के हिसाब से कम सीटें आएंगी।

जहां तक मुख्यमंत्रियों के बयान की बात है तो आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू ने तो यहां तक कह दिया है कि दो से ज्यादा बच्चे वाला व्यक्ति ही स्थानीय निकाय चुनाव लड़ पायेगा। बताया जा रहा है कि पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी ऐसा कानून लाने की मांग हो रही है ताकि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि लोकसभा परिसीमन प्रक्रिया से कई दंपतियों में "16 (तरह की संपत्ति) बच्चों" की तमिल कहावत की ओर वापस लौटने की उम्मीदें बढ़ सकती हैं। मुख्यमंत्री ने जनगणना और लोकसभा परिसीमन प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि नवविवाहित जोड़े अब कम बच्चे पैदा करने का विचार त्याग सकते हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में बुजुर्ग नवविवाहित जोड़ों को 16 बच्चों का नहीं बल्कि 16 तरह की संपत्ति अर्जित करने और खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देते थे, जिसमें प्रसिद्धि, शिक्षा, वंश, धन आदि शामिल हैं।

प्रकृति की गोद से लिखी जाएगी सरगुजा क्षेत्र के विकास की नई इबारत

मुख्यमंत्री साय खड़सा व्यू प्वाइंट से नौका विहार करते मयाली नेचर कैंप बैठक स्थल तक पहुंचे

■ पारंपरिक वाद्य यंत्रों और बांस की टोपी व जंगली फल पत्तियों की माला से हुआ स्वागत

जशपुर। प्रकृति की गोद से आज सरगुजा क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। जशपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मयाली में आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित है। जिसमें शामिल होने खड़सा व्यू प्वाइंट पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं सभी अतिथियों का कर्मा नृत्य और पारंपरिक वाद्य यंत्रों ढांक एवं नगाड़े की धुनों के बीच परम्परागत बांस की टोपी और डुंबर के फल और आम की पत्तियों की माला पहना कर स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय खड़सा व्यू प्वाइंट से बैठक में शामिल होने मयाली डैम में बोट से सभी अतिथियों के साथ मयाली नेचर कैंप की खूबसूरती को निहारते हुए बैठक स्थल तक पहुंचे।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के साथ बैठक में शामिल होने स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा, उपाध्यक्ष सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण श्रीमती गोमती साय, सांसद रायगढ़ श्री राधेश्याम राठिया, विधायक जशपुर श्रीमती रायमुनी भगत, श्री राम प्रताप सिंह, श्री कृष्ण कुमार राय, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, कमिश्नर श्री जी आर चुरेंद्र, आईजी श्री अंकित गर्ग, कलेक्टर डॉ रवि मित्तल, एसपी श्री शशिमोहन सिंह भी पहुंचे।

नेचर कैंप से एक ओर डैम की खूबसूरती तो दूसरी ओर विशालतम प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ का विहंगम दृश्य और दिखाई पड़ता है। चारों ओर फैली हरियाली इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। मयाली नेचर कैंप को स्वदेश दर्शन योजना में शामिल करने के साथ ही पर्यटन विभाग ने मयाली के विकास के लिए 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जशपुर की सुरम्य पहाड़ियों की गोद में स्थित है प्रकृति का अनुपम उपहार मयाली। यहां मयाली नेचर कैंप जिले के कुनकुरी ब्लॉक में चराईडांड़ बगीचा स्टेट हाईवे के करीब स्थित है। डेम के किनारे, हरियाली से भरे हुए प्राकृतिक स्थल पर परिवार के साथ भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। वीकेंड के दिनों में मयाली में लोगों की भीड़ ज्यादा जुटती है। मयाली नेचर कैंप में बोटिंग की भी सुविधा है।

रिश्वतखोर बाबू के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई तेज

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के चर्चित रिश्वतखोर बाबू सतेंद्र सिन्हा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की कार्रवाई फिर से तेज हो गई है। एसीबी की नौ सदस्यीय टीम एक बार फिर मनेन्द्रगढ़ पहुंची। जहां उसने सतेंद्र सिन्हा और उनके परिजनों के बैंक खातों और लॉकरों की जांच की। टीम का मुख्य उद्देश्य सिन्हा की अनुपादित संपत्ति की जांच करना था।

इस कार्रवाई में सबसे पहले टीम ने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में सतेंद्र सिन्हा के लॉकर की जांच की। इस दौरान टीम ने करीब डेढ़ घंटे तक दस्तावेजों और नकदी से जुड़े सवालों पर पूछताछ की। इसके बाद एसीबी की टीम एक्सिस बैंक पहुंची, जहां सतेंद्र सिन्हा के साले के खाते की जांच की गई। हालांकि, बैंक लॉकर से कोई खास जानकारी नहीं मिली, जिसके कारण टीम ने बिना ज्यादा देर किए बैंक से निकलने का फैसला किया।

एसीबी के डीएसपी प्रमोद कुमार खेस ने बताया कि सतेंद्र सिन्हा के खिलाफ अनुपादित संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। टीम ने ग्रामीण बैंक और एक्सिस बैंक में सतेंद्र और उनके परिवार के खातों और लॉकरों की जांच की। हालांकि, अभी तक लॉकर से कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं मिला है।

डीएसपी प्रमोद कुमार खेस ने कहा सतेंद्र सिन्हा

के पास काफी मात्रा में अचल संपत्ति पाई गई है। करीब 10 से 12 मकान मिले हैं, जिनका मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी से कराया जाएगा।अभी तक 10 करोड़ रुपए की संपत्ति सामने आई है, लेकिन जांच अभी जारी है, जिससे संपत्ति का और भी बड़ा आंकड़ा सामने आ सकता है।

डीएसपी प्रमोद कुमार खेस ने बताया कि जांच में सामने आया है कि ग्रामीण बैंक के लॉकर में करीब 1 लाख रुपये थे, जिन्हें 18 तारीख को ही जब्त कर लिया गया था। वहीं एक्सिस बैंक के लॉकर में सतेंद्र सिन्हा के साले के खाते में मात्र 10 हजार रुपये थे,जिसके कारण उनके ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हुई।मामले में अभी कई पहलुओं पर जांच जारी है, और आने वाले दिनों में और भी खुलासे हो सकते हैं।

नक्सलगढ़ में बन रही फर्राटेदार सड़क गांव वाले भी माओवादियों के खिलाफ

नारायणपुर। नक्सलगढ़ में हमेशा से नक्सली सड़क बनाए जाने का विरोध करते रहे हैं। नारायणपुर सोनपुर छोटेबेठिया में भी सालों से नक्सली सड़क बनने नहीं दे रहे। सड़क बनाने का काम जब भी शुरु होता माओवादी गांव वालों को भड़का देते। पर अब गांव वाले समझ गए हैं। उनको पता चल गया है कि नक्सली क्यों सड़क नहीं बनने दे रहे। सरकार ने जब दोबारा सड़क बनाने का बात कही तब गांव वालों ने सड़क बनाने का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि ये भी बताया कि सड़क उनके लिए कितनी जरुरी है। सड़क बनने से मरीजों को शहर ले जाने में आसानी होगी। मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा। गांव के युवा रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जा सकेंगे। किसान अपनी फसलों को मंडी तक ले जा सकेगा।

जिस नक्सलगढ़ में नक्सली सड़क नहीं बनने दे रहे थे वहां पर अब गांव वालों की मदद से सड़क का काम शुरु हो चुका है। गांव वालों का कहना है कि पहले होराडी गांव में एक पुरानी टूटी फूटी सड़क थी जिसका इस्तेमाल नारायणपुर सोनपुर छोटेबेठिया आने जाने वाले लोग करते थे। बारिश और रात के वक्त इस सड़क से गुजरना मुश्किल होता था।

नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार कहते हैं कि नक्सलवाद के चलते विकास का काम इन इलाकों में ठप था। होराडी गांव में एक पुरानी सड़क है जो 1950 के आस पास बनी थी। वो सड़क नारायणपुर सोनपुर छोटेबेठिया को जोड़ती है। सड़क नहीं होने के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम सड़क बनाने का काम हो रहा है।

पहले यहां के लोग नक्सलियों के डर से सड़क का विरोध करते थे। अब वही लोग सड़क बनाने का समर्थन कर रहे हैं।

एसपी प्रभात कुमार ने कहा नक्सल प्रभावित होराडी गांव तक आज सड़क पहुंच गई है। सरकारी सुविधाएं और सरकारी स्कीम यहां के लोगों को मिल रही है। पुलिस शिविर के जरिए भी लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। जिला पंचायत सीईओ वासु जैन ने कहा होराडी के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलने लगी है। सड़क का निर्माण भी हो रहा है। अब यहां की तस्वीर बदल चुकी है।

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्रीय गृहमंत्री के निर्देशों पर एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम आने वाले दो सालों के भीतर नक्सल समस्या को खत्म कर दम लेंगे। रमन सिंह ने कहा कि बीते दिनों नारायणपुर में आईईडी धमाकों में आईटीबीपी के दो जवान शहीद हो गए। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द बाकी बचे माओवादियों का खात्मा किया जाए। एंटी नक्सल ऑपरेशन के अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं।

खस्ताहाल नहरों ने बढ़ाई किसानों की चिंता

सिंचाई विभाग का दावा जल्द होगी सफाई

कोरिया। जिले में अब धान के फसल की कटाई शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद किसान अपनी खेतों में गेहूं फसल की उपज करने की तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन धान की फसल की तरह गेहूं की फसल भगवान के भरोसे नहीं किया जा सकती। गेहूं की फसल के लिए पर्याप्त सिंचाई की जरुरत होती है।कोरिया जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र में सिंचाई के सुविधा बनाने के लिए दो बड़े बांध झुमका जलाशय और गेज बांध का निर्माण कराया गया था। जिससे निकलने वाली नहर से किसान गेहूं की फसल की उपज आसानी से कर लेता था। लेकिन जल संसाधन विभाग की वर्षों से हो रही लापरवाही के कारण अब इन दोनों बांधों से निकलने वाली नहरों का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है।

बात करें झुमका जलाशय से निकलने वाली नहर की तो झुमका जलाशय से निकली नहर मझगांव ग्राम से नरकेली ग्राम तक तो सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी पहुंच जाता है। लेकिन जब ये नहर थोड़ी से आगे नरसिंहपुर

ग्राम तक सिंचाई का पानी पहुंचाने में कुछ वर्षों से पूरी तरह नाकाम साबित हो रही।इसी तरह नरकेली ग्राम में भी कई जगह इस नहर का अस्तित्व खत्म हो चुका है। नहर क्षेत्र में पक्के भवन का निर्माण हो चुका है। जिसके कारण झुमका जलाशय से निकलने वाली नहर का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर हैं।वहीं इस बारे में अधिकारियों से पूछने पर उन्होंने नहर की मरम्मत और अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही है।

कई जगहों पर नहर अदृश्य हो चुकी है। वहीं कई जगहों पर नहर के ऊपर ही भवन का निर्माण देखने को मिल जाएगा। नहर के बैंक में बड़े-बड़े पेड़ उग आए हैं। ऐसे में नहरों की सफाई की सख्त जरुरत है।

अनुविभागीय अधिकारी बीके त्रिपाठी ने कहा अभी बारिश के मौसम के कारण नहरों में कचरा हो गया है जिसकी सफाई कराई जा रही है। वहीं जिन जगहों पर नहर में अतिक्रमण किया है उन्हें नोटिस दिया जा चुका है।

आपको बता दें कि इन नहरों के रखरखाव के लिए बड़ी रकम विभाग ने खर्च किया जाता हैं। साल दर साल इन नहरों का रकबा घटने से इस क्षेत्र में गेहूं की फसल की उपज के रकबे में भी कमी देखने को मिल रही है। कई जगह के किसान नहर से सिंचाई के भरोसे गेहूं की खेती करना लगभग छोड़ ही चुके हैं।

बलौदाबाजार आगजनी केस देवेंद्र यादव को नहीं मिली राहत

4 नवंबर तक बढ़ी रिमांड

बलौदाबाजार। आगजनी केस में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यावद की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही है। विधायक देवेंद्र यादव के वकील अनादि शंकर मिश्रा ने कहा कि 21 अक्टूबर को थाना सिटी कोतवाली की पुलिस के द्वारा भिलाई नगर विधायक देवेन्द यादव के विरुद्ध दर्ज किए गए अपराध में आरोप पत्र प्रस्तुत ना करते हुए पुनः आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए समय की मांग की गई, जिस पर विधायक को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच कुल 7 मिनट तक सुनवाई चली। पुलिस को रिमांड दिए जाने पर देवेंद्र यादव और उनके वकील ने इसका विरोध किया। देवेंद्र यादव की वकील अनादि शंकर मिश्रा ने कहा कि 21 अक्टूबर को सुनवाई के बाद विधायक देवेंद्र यादव की रिमांड बढ़ा दी गई। वकील ने आगे बताया कि हाई कोर्ट में जमानत याचिका के लिए आवेदन किया हैं। इसकी सुनवाई 13 नवंबर को होगी।

बलौदाबाजार हिंसा मामले में दोषी बनाए गए विधायक देवेंद्र यादव की बारहवीं पेशी 21 अक्टूबर सोमवार को बलौदाबाजार सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। सुरक्षा की दृष्टि को देखते देवेंद्र यादव की ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट कर पेशी हुई। पुलिस ने देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की थी। जिसमे देवेंद्र यादव के वकील अनादि शंकर मिश्रा ने आपत्ति दर्ज की। जिस पर कोर्ट ने उनकी रिमांड 4 नवंबर तक बढ़ा दी है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

प्रशांत ठाकुर बनाए गए सूरजपुर जिले के नए कप्तान

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सूरजपुर डबल मर्डर के बाद जिले के एसपी को बदल दिया गया है। प्रशांत ठाकुर को जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। पुलिस विभाग ने देर रात तबादला आदेश जारी किया। एम आर अहिरे को पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद पुलिस कप्तान को बदला गया है। घटना 13 अक्टूबर 2024 की है। उस दिन रात आरोपी कुलदीप साहू ने सूरजपुर में पुराने बस स्टैंड में आरक्षक घनश्याम सोनवानी पर कड़ाही का खौलता तेल फेंक दिया था. इस घटना में आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए तत्काल थाने को सूचना दी गई. प्रधान आरक्षक तालिब शेख, उदय सिंह और अन्य पुलिसकर्मी पुराना बस स्टैंड और आसपास आरोपियों की पतासाजी में जुट गए। इसी दौरान आरोपी कुलदीप साहू ने अपने साथियों के साथ रात करीब 10 बजे पुलिसकर्मियों को कार से कुचलने की कोशिश की। पुलिसकर्मी किसी तरह बच गए और कार का पीछा करने लगे।

स्वास्थ्य संयोजकों का ऑनलाइन काम बंद

कबीरधाम। मंगलवार से कबीरधाम जिले के

सभी स्वास्थ्य संयोजक विभाग के ऑनलाइन कार्य नहीं करेंगे। ऐसे में आम लोगों की ऑनलाइन कार्य को लेकर परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल, पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य संयोजकों द्वारा आज से ऑनलाइन काम से दूरी बनाई गई है। जिलाध्यक्ष गोलूराम सोनवानी ने बताया कि ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (क्लिनिकल/नर्सिंग संवर्ग) के कर्मचारियों से मूल कार्य के अतिरिक्त कराए जा रहे कार्य जैसे- डेली एंट्री, आईडीएसपी, सीबेक , यूवीन ,अनमोल एंट्री, टेलिकन्सल्टेशन, हेल्थ मेला,बर्थ रजिस्ट्रेशन, सिकलीन एंट्री , आयुष्मान कार्ड ऑनलाइन डाटा एंट्री के संबंध मे होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए 15 दिवस मे चर्चा कर निराकरण करने संबंधी मांग की गई थी। साथ ही निराकरण नहीं होने की स्थिति मे मूल कार्य के अतिरिक्त होने वाले सभी प्रकार के ऑनलाइन डाटा एंट्री कार्य बंद करने संबंध में अल्टीमेटम दिया गया था।

सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में दूसरे ट्रेलर ने मारी टक्कर

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बीती रात सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में सो रहे खलासी की उस वक्त मौत हो गई जब एक अन्य कोयला लोड़ ट्रेलर चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उस ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुर थाना नवाडीह, पलामू झारखण्ड जिले के रहने वाले दीपक पासवान और उसका बडा भाई अनितेश पिछले तीन सालों से रायगढ़ के किरोड़ीमल क्षेत्र में रहते हुए ट्रेलर चलाने का काम करते थे। सोमवार की रात ट्रेलर चालक अनितेश पासवान और खलासी उसका भाई दीपक पासवान ट्रेलर क्रमांक सीजी 13 ए वी 8706 में फ्लाईएश लेकर तमनार क्षेत्र में स्थित डोंगामहुआ गांव लेकर जा रहे थे। इसी बीच तमनार की तरफ से कोयला लेकर आ रहे ट्रेलर क्रमांक सीजी 22 एक्स 7176 के चालक ने तेज एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़े ट्रेलर को जोरदार ठोकर मारते हुए उसके ही उपर पलट गया। जिससे उक्त ट्रेलर के सामने का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

इमारती लकड़ी की तस्करी करते पिकअप वाहन जब्त

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज गेम रेंज कोदौरा के अंतर्गत इमारती लकड़ी अंबिकापुर अवैध रूप से पिकअप में लोड कर बिक्री के लिए ले जाने की सूचना पर देर रात्रि वन अधिकारियों की मिली। तत्काल रेंजर अजय सोनी के नेतृत्व में सरगावा जंगल से तस्करी करते पिकअप वाहन को पकड़ा। जिसमें साल प्रजाति का सात नग लट्ठा था। जिसकी कीमत करीब 60 हजार रुपये के करीब आकी जा रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार के मध्य रात्रि गेम रेंज कोदौरा के रेंजर अजय सोनी के द्वारा मुखबिर की सूचना पर दो टीम का गठन किया। देर रात सरगावा जंगल से एक पिकअप आता दिखाई दी। जिसे ग्रामीणों की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसमें सात नग साल प्रजाति का लट्ठा था। जिसकी कीमत 60000 रुपए के करीब आकी जा रही है। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हो गए। वन अधिनियम के तहत वन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

ग्राम हाथीबेड़ में लगाया गया ट्रांसफार्मर

जशपुर। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया की पहल पर फरसाबहार तहसील के ग्राम हाथीबेड़ में ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है। इससे बिजली आपूर्ति पुनः बहाल हो गई है। ग्राम हाथीबेड़ के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में आवेदन दिया था कि ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित है। कैंप कार्यालय के निर्देश पर तत्काल ट्रांसफार्मर बदल दिया गया है। ग्रामीणों ने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर बगिया में खोले गए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में लोगों की मांगों और समस्याओं के सामाधान का क्रम सतत रूप से जारी है। कैंप कार्यालय के निर्देश पर समस्या आने पर तत्काल ट्रांसफार्मर लगाने, ग्रिप चेंज, लाईन सुधारने का कार्य किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। जशपुर हाथी विचरण क्षेत्र होने की वजह से मुख्यमंत्री श्री साय के द्वारा बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मातृभूमि की रक्षा और देश सेवा सर्वोपरिः आईजी झा

पीटीएस के 81वें दीक्षांत समारोह में 104 नवआरक्षकों ने ली शपथ

राजनांदगांव। पीटीएस में मंगलवार को 81वें नवआरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण के दीक्षांत समारोह में 104 नव आरक्षकों ने कर्तव्यनिष्ठा की शपथ ली। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि आईजी दीपक झा ने आरक्षकों को संबोधित करते कहा कि बुनियादी प्रशिक्षण की पूर्णता पर श्रेष्ठ दीक्षांत परेड रही और मातृभूमि की रक्षा और देश सेवा सर्वोपरि है। यह अवसर जीवन में एक बार ही आता है। आईजी ने कहा कि शपथ के एक-एक शब्द का पूर्ण समर्पित भाव, निष्ठा एवं निष्पक्षता से नवआरक्षक पालन करेंगे। यह शपथ चुनौतीपूर्ण कार्यों के वक्त

यह निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करेगा।

आईजी ने उम्मीद जताई कि दीक्षांत समारोह के बाद मूल इकाई में जाकर जनसुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में नव आरक्षक अपनी भूमिका का बेहतर निर्वहन करेंगे। मुख्य अतिथि की आसंदी से उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों और परिजनों को शुभकामनाएं देते अपने अनुभव भी साझा किए। इससे पहले नवआरक्षकों ने मार्चपास्ट किया। आईजी दीपक झा ने मार्चपास्ट की सलामी ली। 81वें दीक्षांत समारोह में कुल 104 नव आरक्षकों ने प्रशिक्षण लिया। दीक्षांत समारोह में प्रशिक्षणार्थी नवआरक्षकों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। जिसमें 104 नव आरक्षकों में सुकमा जिले 56, बीजापुर से 28 एवं जिला दन्तेवाड़ा से 20 नवआरक्षक शामिल हुए। इनमें 5 नवआरक्षक सीधी भर्ती के 27 अनुकम्पा नियुक्ति से 9 गोपनीय सैनिक एवं 63 सहायक आरक्षक शामिल थे।

दीक्षांत परेड कार्यक्रम में आईजी दीपक झा के द्वारा प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर एसपी मोहित गर्ग, उप सेनानी प्रशांत कतलम, एएसपीद्वय मुकेश ठाकुर, राहुलदेव शर्मा, सीएसपी पुष्पेन्द्र नायक, डीएसपी तनुप्रिया ठाकुर, रमेश येरेवार, अजीत ओगरे, आरआई लोकेश कसेर समेत पीटीएस के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में पीटीएस एसपी गजेन्द्र ठाकुर का आईजी ने प्रशंसा की।

डीजल चोर गिरोह पर शिकंजा, गेवरा खदान में 11 सदस्य गिरफ्तार

■ सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल

कोरबा। गेवरा खदान में डीजल चोर सालिक और अजय के गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। गिरोह के 11 लोगों को दीपका थाना पुलिस ने पकड़ा है। जिनके कब्जे से भारी मात्रा में डीजल बरामद किया गया है। एसईसीएल की गेवरा परियोजना खदान से डीजल चोरी की शिकायत पर देर रात मुखबिर की सूचना पर बड़ी डीजल चोरी पकड़ी है।

खदान में चोरी करते हुए डीजल चोर सालिक राम और अजय के गिरोह के कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 11 व्यक्तियों ने खदान में खड़े वाहनों और मशीनों से 2659 लीटर डीजल चोरी कर कर भागने के फिराक में थे। जहां जहां दीपका थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू और पूरी टीम ने देर रात खदान में जान जोखिम में डाल छापा मारा। जिन्हें घेराबंदी कर धरदबोचा। जिनके कब्जे से बोलेरो वाहन और भारी मात्रा में डीजल बरामद किया गया है। जिसकी कीमत कुल कीमत 2,48,456 रुपये बताई जा रही है।

बताया जा रहा कि दीपका पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग बोलेरो वाहनों में डीजल चोरी कर रहे हैं। जहां दीपका थाना मौके पर पहुंची और सूचना मिलते ही सुरक्षा प्रहरी राकेश कुमार सिंह और सुधीर कुमार के साथ वे मौके पर पहुंचे। जहां उन्होंने देखा कि डोजर क्रमांक 906, 194, 145 और डम्पर क्रमांक 4137, 95225 के पास डीजल बिखरा हुआ था। पहले घेराबंदी की और फिर उसके बाद आरोपियों को पकड़ा।

संक्षिप्त समाचार

रायपुर दक्षिण उपचुनाव : सीएम साय ने किया भाजपा की जीत का दावा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा में 13 नवंबर को उपचुनाव होने को हैं। भाजपा की तरफ से इस बार पूर्व सांसद सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस ने अब तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जबकि अन्य 3 निर्दलीय प्रत्याशी उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकर फॉर्म चुके हैं। इस उपचुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा लगातार भाजपा पार्टी का रहा है। बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में 65 हजार से ज्यादा मतों से जीते हैं। अब उपचुनाव में पूर्व सांसद सुनील सोनी वहां से जीतेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलने पर सीएम साय ने कहा कि वे उनका मामला है, हम विपक्ष को मजबूत मानकर ही काम कर रहे हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सरकार बनाई, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल ने रिकॉर्डतोड़ मतों से 8वीं बार रायपुर दक्षिण जीत दर्ज की थी। वे साय केबिनेट में शिक्षा एवं संस्कृति विभाग के मंत्री बने। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायपुर सीट से जीत हासिल की और अब वे रायपुर लोकसभा सांसद बन गए। सांसद चुने जाने के बाद अब रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता अपना विधायक चुनने वाली है। इस उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, हालांकि कांग्रेस भी उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार करने लगातार बैठकें कर रही है। लेकिन जनता किसे जनादेश देगी, यह तो उपचुनाव के बाद ही पता चल सकेगा।

रायपुर क्राइम ब्रांच में एएसआइ, हेड कांस्टेबल समेत 24 हटाए गए

रायपुर। रायपुर क्राइम ब्रांच (अब एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट) में वर्षों से जमे एएसआई,कांस्टेबल और हेडकांस्टेबल समेत 24 कर्मचारियों का तबादला रायपुर रेंज के आइजी अमरेश मिश्रा ने किया है। जारी आदेश में प्रशासनिक आधार पर रेंज स्थापना बोर्ड के निर्णय पर ये तबादला किया गया है। आदेश में क्राइम यूनिट में वर्षों से पदस्थ एएसआई किशोर सेठ, मोहम्मद जमील और मोहम्मद कय्यूम को बलौदाबाजार, संतोष सिंह को धमतरी, मो.इरफान को गरियाबंद भेजा गया है। वहीं हेड कांस्टेबल सरफराज चिश्ती को महासमुंद, अभिषेक सिंह को धमतरी, मोहम्मद सुल्तान को गरियाबंद, कांस्टेबल रवि तिवारी, राहुल शर्मा और मो.राजिक को बलौदाबाजार,आलम मिर्जा को गरियाबंद, सरीम खान, कुलदीप मिंज को धमतरी, अमित यादव को बलौदाबाजार, मुकेश सिंह राजपूत को महासमुंद, कृष्णा ठाकुर को बलौदाबाजार तबादला किया गया है जबकि धमतरी में पदस्थ हेड कांस्टेबल दिनेश तुरकाने, देवेंद्र राजपूत, महिला हेड कांस्टेबल माधुरी सोनवानी को रायपुर, कांस्टेबल कुलदीप सिंह, अंकुश नंदा, खेमू हिरवानी को रायपुर और साजिद अली को बलौदाबाजार भेजा गया है।

शासकीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही मिल जाएगी सैलरी, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों को खुशियों का तोहफा दिया है। सरकार ने दिवाली से पहले ही सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन, मजदूरी, मानदेय, पारिश्रमिक भुगतान करने के लिए आदेश जारी किया है। वित्त विभाग मंत्रालय की तरफ से सभी विभागों, अध्यक्ष, राजस्व मंडल, समस्त विभागाध्यक्ष, सभी संभागीय आयुक्त और सभी कलेक्टरों को यह आदेश जारी किया गया है। बता दें, इस साल दीपावली अक्टूबर महीने के अंत में है, जिससे सभी कर्मचारियों को महीने भर के खर्च के बाद त्यौहार मनाने के लिए वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को त्यौहार से पहले सैलरी मिलने से उनके लिए इस त्यौहार की खुशी दुगुनी होने वाली है।

पंडो बहुल्य ग्राम पंचायत में शासकीय राशन दुकान से राशन वितरण में गड़बड़ी

बलरामपुर। शासकीय राशन दुकान से राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत आम है, लेकिन अगर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति बाहुल्य गांव में इस तरह की गड़बड़ी हो तो मामला संगीन हो जाता है। ऐसा ही एक मामला मामला बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत महादेवपुर से सामने आया है। ग्राम पंचायत महादेवपुर स्थित शासकीय राशन दुकान के संचालक द्वारा राशन वितरण में हेरा-फेरी की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि संचालक हर महीने राशन तो देता है, लेकिन तौल में हेरा फेरी भी करता है। तराजू से छेड़छाड़ कर कमोबेश हर हितग्राही को मिलने वाले चावल में डेढ़ से दो किलो कम देता है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार फूड इंस्पेक्टर प्रशांत राजवाड़े से भी शिकायत की है, लेकिन फूड इंस्पेक्टर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। यही नहीं फूड इंस्पेक्टर उन्हें जहां चाहे वहां शिकायत करने की चुनौती देते हुए कहता है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। फूड इंस्पेक्टर की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर का फैसला लिया है। मामले की जानकारी के लिए फूड इंस्पेक्टर से संपर्क किया, तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

24 अक्टूबर को सरगुजा के स्कूलों में लटकेंगे ताले

■ सामूहिक अवकाश पर रहेंगे शिक्षक

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर एकदिवसीय जिलास्तरीय आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। जिसमें राज्यभर के शिक्षकों की विभिन्न मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सामूहिक अवकाश लेकर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिलास्तरीय आंदोलन को लेकर जिला संचालक मनोज वर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का यह आंदोलन शिक्षकों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर है। वेतन विसंगति, पदोन्नति, पेंशन योजना, और महंगाई भत्ते जैसे मुद्दों पर शिक्षकों की मांगें पूरी न होने से उनमे असंतोष का स्तर बढ़ता जा रहा है।

24 अक्टूबर को होने वाले इस एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षक समुदाय अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेगा । इस विज्ञप्ति के माध्यम से जिला संचालक ने जिले के सभी शिक्षकों से 1 दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। मोर्चा के संभागीय संचालक हरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम नियुक्ति तिथि से पूर्व सेवा गणना शिक्षकों की प्रमुख मांगों में एक है कि

उनकी सेवा की गणना उनकी पहली नियुक्ति तिथि से की जाए। इससे शिक्षकों को अपनी सेवा अवधि को बेहतर तरीके से मान्यता मिल सकेगी और इसके आधार पर उन्हें अन्य लाभ भी मिल सकेंगे।

दूसरी मांग सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करना है,सहायक शिक्षकों के वेतन में असमानता को लेकर लंबे समय से शिक्षक असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि इस वेतन विसंगति को तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए ताकि सभी शिक्षकों को समान वेतनमान प्राप्त हो सके। हरेंद्र सिंह ने कहा कि क्रमोन्नति वेतनमान की मांग शिक्षक समुदाय की ओर से यह मांग उठाई गई है कि उन्हें उनके सेवा काल के अनुसार क्रमोन्नति वेतनमान प्रदान किया जाए। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सेवा के दौरान किए गए योगदान के लिए मान्यता मिलेगी। साथ ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली - शिक्षकों की यह भी मांग है कि उनकी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। वर्तमान में लागू नई पेंशन योजना के अंतर्गत शिक्षकों को पुरानी पेंशन के बराबर लाभ नहीं मिलते हैं, जिससे शिक्षक असंतुष्ट हैं। इसलिए, शिक्षक चाहते हैं कि उन्हें उनकी पहली नियुक्ति तिथि के आधार पर पुरानी पेंशन योजना के लाभ दिए जाएं।

शिक्षकों की यह भी मांग है कि 20 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें सम्पूर्ण पेंशन का अधिकार दिया जाए। यह मांग उनकी सेवा की स्थिरता और सुरक्षा को लेकर की जा रही है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। रिक्त पदों पर पदोन्नति - कई स्तरों पर शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिससे पदोन्नति की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है। शिक्षक चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन रिक्त पदों पर पदोन्नति की जाए ताकि योग्य शिक्षकों को उनके योग्यता के अनुसार पदोन्नति मिल सके।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डबल बैंच द्वारा दिए गए क्रमोन्नति संबंधी निर्णय को सभी शिक्षकों पर लागू करने की मांग की जा रही है। शिक्षकों का कहना है कि इस निर्णय से सभी शिक्षकों को लाभ मिलना चाहिए। लंबित महंगाई भत्ता और एरियर्स का भुगतान- शिक्षकों के महंगाई भत्ते का भुगतान समय पर नहीं हुआ है, जिससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए वे लंबित महंगाई भत्ता जल्द से जल्द जारी करने और देय तिथि से एरियर्स राशि का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। सरगुजा जिले के सभी विकासखंडों में शिक्षकों द्वारा हड़ताल में शामिल होने की सूचना दी जा रही है। गौरतलब है कि सरगुजा में संविलियन के पश्चात शिक्षकों का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है।

35 दिनों से हड़ताल पर कंप्यूटर ऑपरेटर, मंत्री बंगला पहुंचे ऑपरेटरों को पुलिस ने खदेड़ा

■ अध्यक्ष बोले- मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन

रायपुर। छत्तीसगढ़ धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ दो सूत्रीय मांगों को लेकर 35 दिनों से हड़ताल पर हैं। अब तक कोई पहल नहीं होने पर ऑपरेटर आज मंत्री ह्रक चौधरी के बंगला पहुंचे थे, जहां फरियादियों की मांग की सुनवाई नहीं हुई, लेकिन बंगले के पास से पुलिस ने जेल भेजने की धमकी देते हुए ऑपरेटरों को खदेड़ दिया।

धान खरीदी कम्प्यूटर आपरेटर संघ के अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने कहा, धरना स्थल में ताला लगा दिया गया है। हम कहां अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन करें। आज मंत्री ह्रक चौधरी के बंगला पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने धमकी चमकी देते हुए जेल भेजने की धमकी दी और वहां से खदेड़ दिया। अब हम अपनी मांग कहां करें? किससे करें?

आपरेटर संघ के अध्यक्ष मोहरे ने

कहा, अनिश्चितकालीन हड़ताल को कुचला जा रहा है। 18 सितंबर 2024 से छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। आज आंदोलन का 35वां दिन है। चाहे सरकार, पुलिस जो भी कर ले हम अपनी हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। अपनी मांग लेकर रहेंगे।

उन्होंने कहा, कर्मचारी-अधिकारी अलग-अलग कैटेगिरी के हो सकते हैं, लेकिन उनका विभाग तय होता है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि धान ख़रीदी करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर पिछले 17 सालों से काम कर रहे हैं पर उनका विभाग तय नहीं है। 6-7 अलग अलग विभाग उनसे काम लेते हैं।

2007 से समर्थन मूल्य धान खरीदी के कंप्यूटरीकरण वर्ष से विगत 17 वर्षों से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर का विभाग तय किया जाए व उन्हें नियमित किया जाए। दूसरा शासन के वित्त निर्देश में जारी 27 परसेंट वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इन्हीं दो मुद्दों को लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे।

कप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल से सोसाइटी में धान खरीदी के लिए पंजीयन पूर्णता बाधित है। सोसाइटी पूर्णतया ऑफलाइन हो गई है, जिससे किसानों को पंजीयन कराने भटकना पड़ रहा है। सभी सोसाइटी के ऑपरेटर हड़ताल में है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि धान ख़रीदी कैसे होगी ?

मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे से एडमिशन लेने वाले छात्रों को बड़ी राहत

हाई कोर्ट का आदेश- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश नहीं होगा लागू

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से दाखिला लेने वाले छात्रों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एनआरआई कोटे के एडमिशन निरस्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू नहीं हो सकता। इसे कानून मानकर किसी नियम को लागू नहीं किया जा सकता।

छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे से ही रही भर्ती पर सवाल उठने के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 18 अक्टूबर को आदेश जारी कर एनआरआई कोटे से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने के

आदेश को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए एनआरआई कोटे से एडमिशन लेने वाले छात्र अंतश तिवारी सहित 40 अन्य छात्रों ने अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा व अनुराग श्रीवास्तव के माध्यम से हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी।

याचिकाकर्ता छात्रों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि छत्तीसगढ़ मेडिकल एजुकेशन प्रवेश नियम 2008 के तहत एनआरआई कोटे की सीटें तय की गई है, जिसके आधार पर एनआरआई छात्रों को एडमिशन दिया गया है। लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा एनआरआई कोटे के नियम में किए गए बदलाव को आधार मानते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अफसरों ने बिना विधिक सलाह लिए एनआरआई कोटे के छात्रों का प्रवेश निरस्त कर दिया है, जो असंवैधानिक है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता से विधिक अभिमत मांगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का एसएलपी और पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होगा। एजी प्रफुल्ल भारत ने कहा यह कोई कानून नहीं है। इस अभिमत के आधार पर हाईकोर्ट ने एनआरआई छात्रों के प्रवेश निरस्त करने के आदेश को खारिज कर दिया है।

कांकेर जिले की मासुलपानी पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर मिला द्वितीय पुरस्कार

■ नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में केंद्रीय जलमंत्री सीआर पाटिल ने किया पुरस्कृत

रायपुर। जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कांकेर जिले की ग्राम पंचायत मासुलपानी को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय जलमंत्री श्री सीआर पाटिल द्वारा ग्राम पंचायत मासुलपानी की सरपंच श्रीमती रमिया नेताम को पुरस्कृत किया।

गौरतलब है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में मासुलपानी पंचायत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। इस ग्राम पंचायत में 161 जल शेड संरचनाएं बनाई गई हैं, जिनमें 99 फार्म तालाब शामिल हैं। इसके अलावा, वर्ष 2023 के दौरान पंचायत द्वारा 39 नंबर ब्रशवुड, एक सामुदायिक तालाब डी-सिल्टिंग, 02 कुएं, 02 भूमिगत बांध, 03 गेबियन और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके चलते लोगों ने सिंचाई के लिए सतही जल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। जल संरक्षण और इसके समुचित उपयोग की दिशा में इस

नवाचार के लिए मासुलपानी ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और लोगों को सर्वोत्तम जल उपयोग प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार (एनडब्ल्युए) देश भर में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा जल समृद्ध भारत के सरकार के विजन् को प्राप्त करने में किए गए अच्छे काम और प्रयासों पर केंद्रित है। ये पुरस्कार लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं।

खाद्य संचालनालय से अपर संचालक जायसवाल हटाए गए

रायपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के कार्यकाल में 600 करोड़ रुपये के राशन घोटाले मामले में शासन ने खाद्य संचालनालय के अपर संचालक राजीव कुमार जायसवाल को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश जारी करते हुए उन्हें संयुक्त सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया है। यह आदेश 18 अक्टूबर को सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है।

उल्लेखनीय हैं कि कांग्रेस शासनकाल में हुए इस राशन घोटाले के मामले को पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डा. रमन सिंह ने विधानसभा में उठाया है और इसमें संचालनालय के अधिकारी के शामिल होने की जानकारी दी थी। कांग्रेस शासनकाल में निष्पक्ष जांच न होने की आशंका में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय को सप्रमाण पत्र भी लिखा था। इस मामले को उजागर न होने से बचाने के लिए अनेक तरीकों का इस्तेमाल किया गया जिसमें तेरह हजार राशन दुकानों के घोषणा पत्र गायब कर दिया गया जिसके चलते खाद्य विभाग सहित प्रदेश के तेरह हजार राशन दुकानदार हड़ताल पर चले गए थे।

करोड़ो के राशन बचत घोटाले को लेकर नई सरकार के बजट सत्र में सदन में जोरदार हंगामा हुआ था। इसके चलते राशन बचत घोटाले के लिए पूर्व खाद्य मंत्री पुनर्लाल मोहिले के सभापतित्व में पांच सदस्यीय जांच समिति बैठा दी गई है। इस समिति के सामने विभाग के अधिकारियों ने मांग किया था कि राजीव कुमार जायसवाल के खाद्य संचालनालय में कार्य करते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। आज सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर राजीव कुमार जायसवाल को अपर संचालक खाद्य संचालनालय से हटा कर नीलिमा एल्मा को मंत्रालय से संचालनालय में अपर संचालक पदस्थ किया है। इस आदेश का हमर संगवारी के अध्यक्ष राकेश चौबे ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों के अनाज का घोटाला करने वाले अधिकारी के विरुद्ध प्रयाप्त प्रमाण है जिसके आधार पर गिरफ्तारी होना चाहिए।

पीएम किसान समृद्धि सह योजना के तहत एनएफडीपी पर पंजीकरण अनिवार्य

■ मत्स्य कृषकों से पंजीयन कराने की अपील

रायपुर। मत्स्य कृषकों को केन्द्र शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत् विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने के लिए एनएफडीपी पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। संचालक मछली पालन श्री नारायण सिंह नाग ने बताया कि एनएफडीपी का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों एवं मत्स्य समितियों के लिए कार्य आधारित पहचान का डाटाबेस निर्माण के माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना है। भविष्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत् मत्स्य पालन अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु एनएफडीपी पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके तहत मछली पालन, मत्स्याखेट एवं मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) के माध्यम से किया जा सकेगा।

संचालक श्री नाग ने बताया

कि यदि परिवार के सभी सदस्य मछली पालन कार्य में संलग्न है, तो सभी का पंजीयन व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा।

पंजीयन के बाद मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात उनके बैंक खातों में 80 रूपये शासन की ओर से प्राप्त होगा तथा कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) को उनके प्रत्येक एन्ट्री पर 18 रूपये कमीशन के रूप में प्राप्त होगा। पंजीयन हेतु मत्स्य कृषकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा आधार लिंक मोबाईल नम्बर के साथ कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) में एन्ट्री कार्य कराया जाना है। पंजीयन हेतु आधार लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी अनिवार्य होगा। पंजीयन के बाद प्रारम्भ में अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। कृषकों का मत्स्य विभाग से सत्यापन पश्चात स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

पीएम डिजिटल साक्षरता अभियान से प्रेरित होकर डिजिटल बस की शुरुआत

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में सक्षम सूरजपुर अभियान अंतर्गत जिला प्रशासन ने एक अभिनव पहल कर सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर साक्षरता दर बढ़ाने हेतु डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेन (डिजिटल बस) का इनदिनों दूरस्थ अंचल क्षेत्रो में संचालन करा रही है। 20 कंप्युटर से लैस यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेन (डिजिटल बस) की ख़ासियत यह है कि ये लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें कंप्यूटर और डिजिटल माध्यम से संबंधित बुनियादी शिक्षा से परिचित करवायेगी। जिससे जुड़ कर अभ्यर्थी व आमजन डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनेंगे। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेन एन.आई.आई.टी. फाउंडेशन द्वारा संचालित तथा इंडस टावर द्वारा वित्त पोषित है।

सूरजपुर में सक्षम सूरजपुर अभियान अंतर्गत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेन (डिजिटल बस) के माध्यम से दूरस्थ ग्राम अंचलों में 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान किया जायेगा। जिसमें युवा से लेकर अन्य आयु वर्ग के लोगों का पंजीयन कर उन्हें डिजिटल साक्षरता, बेसिक आईटी शिक्षा और साइबर सिक्योरिटी में सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाएंगें। इसके साथ ही कोर्स को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले

अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा।

प्रदेश का पहला जिला है सूरजपुर जहां डिजिटल बस चल रही है। जो की पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। इस डिजिटल बस में 20 कम्प्यूटर सिस्टम लगे हुए है। जिससे एक ही समय में 20 अभ्यर्थियों को एक साथ डिजिटल, शिक्षा का लाभ दिया जा सकता है। वही सूरजपुर जिले के अतंर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रतिमाह 07 से 08 स्थानों को चिन्हित कर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेन के माध्यम से लगभग 150 से 160 अभ्यर्थियों को डिजिटल साक्षरता से जोड़ने का प्रयास संस्था द्वारा किया जा रहा है। यह डिजिटल बस पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी। इसके साथ ही शनिवार व रविवार के दिन सामूहिक साक्षरता के माध्यम से भी डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाएगा।

सूरजपुर जिले में 06 माह की अवधि तक डिजिटल बस अपनी सेवा देगी। जिसमें लगभग 1000 लोग डिजिटल साक्षरता अभियान से जुड़कर लाभान्वित होंगें। वही अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 500 से अधिक बच्चों का पंजीयन हो चुका है। जिनसे दो बैंच निर्मित किये गए है। शुरूआती रूट चार्ट अतंर्गत सूरजपुर जिले अतंर्गत में कोट, आमगांव, पटना, पस्ता, सोनपुर में डिजिटल बस चलेगी। जिसका दायरा समय अनुसार बढ़ता जायेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेन (डिजिटल बस) द्वारा डिजिटल बैंकिंग से लेकर साईबर सिक्योरिटी की मिलेगी। शिक्षा- सक्षम सूरजपुर अतंर्गत चलने वाली यह डिजिटल बस मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रवासियों को सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर से संबंधित तकनीकी ज्ञान से अवगत कराते हुए साक्षर बनाएगी। डिजिटल साक्षरता के अतंर्गत अभ्यर्थियों को डिजिटल बैकिंग, इन्टरनेट ब्राउजिंग, ईमेल का उपयोग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और बढ़ते हुये साइबर फ्रॉड से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी शिक्षा दी जाएगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेन(डिजिटल बस) में कुल 20 कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं, जिसके माध्यम से एक ही समय में 20 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षार्थियों को निर्बाध सेवा प्राप्त हो इसके लिए डिजिटल बस में कंप्यूटर सिस्टम के साथ-साथ एलईडी टीवी, डिजिटल बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्बाध संचालन के लिए जनरेटर व सोलर पैनल भी स्थापित है। इसके साथ ही बस का प्रशिक्षण कक्ष वातानुकूलित है। बस में एक एलईडी टीवी बाहर की ओर लगा है, जिसका उपयोग सामूहिक साक्षरता कार्यक्रम के लिए किया जायेगा।

कलेक्टर रोहित व्यास ने आज के समय को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का युग का है। बच्चों को समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने हेतु उक्त बस के माध्यम से प्रेरित किया। साथ जिलेवासियों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेन से जुड़ने की अपील की। ताकि गांव-गांव तक जाने वाली इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेन से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लोग लाभांवित हो सकें।

कांग्रेस ने खड़े किए हाथ, उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेगी उपचुनाव

अजय कुमार

यूपी में होने वाले विधान सभा के उप चुनाव में एनडीए और इंडी गठबंधन में शमिल राजनैतिक दलों के बीच मतभेद खुलकर समाने आ गया है। चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपर हैंड में नजर आ रही हैं। वहीं देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के सामने तो संजय निषाद की पार्टी को बीजेपी नेताओं के सामने सीटों के लिये चिरौरी करना पड़ रही है। कांग्रेस का तो यह हाल है कि वह यही नहीं समझ पा रही है कि चुनाव लड़े या नहीं। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के समय यूपी में हुआ सपा व कांग्रेस का गठबंधन तो बना रहेगा पर कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में एक भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ऐसा इसलिये नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच का जोश किसी वजह से फीका पड़ जाये। कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने की जो सबसे बड़ी बात समझ में आ रही हैं उसके अनुसार कांग्रेस को अपने हिस्से आईं खैर व गाजियाबाद सीटों पर भाजपा से मुकाबला करना आसान नहीं दिख रहा है। माना जा रहा है कि इसके चलते ही कांग्रेस अब इन दोनों सीटों को भी सपा की झोली में डालने का मन बना चुकी है। वैसे कुछ लोग इस बात की भी आशंका जता रहे हैं कांग्रेस ने सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने की वजह से अपने आप को चुनाव की रेस से बाहर किया है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जल्द ही चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा हो जाएगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की नजर उप चुनाव पर नहीं आने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इसलिए कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली जीत से कार्यकर्ताओं में उपजे हौसले को बरकरार रखना चाहती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उपचुनाव में हार से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। पार्टी के लिए यह समय संगठन को मजबूत करने व कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाए रखने का है। कांग्रेस का मुख्य मकसद भाजपा को हराना है और इसके लिए कांग्रेस सभी सीटों पर सपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी यह संदेश केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी। आईएनडीआईए में शामिल सहयोगी दलों से कांग्रेस की खींचतान भी देखने को मिलती रही है। लोकसभा चुनाव में सपा ने 80 में से केवल 17 सीटें कांग्रेस को दी थीं। कांग्रेस इनमें से सात सीटें जीतकर अपनी साख बचाने में कामयाब रही थी और अब प्रदेश में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। कांग्रेस दो सीटें छोड़कर सहयोगी दलों को अपने त्याग का संदेश भी देना चाहेगी। उधर,यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव के लिए पांच सीटों पर दावेदारी का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को दिया था। सपा के सात सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने के बाद यह पूरी तरह से साफ हो गया था कि उत्तर प्रदेश में साइकिल वाले दल का पलड़ा भारी है। कांग्रेस ने उसके हिस्से आईं दो सीटों को बदलवाने का प्रयास भी किया पर बात नहीं बनी। कांग्रेस ने खैर व गाजियाबाद के बदले फूलपुर व मझवां सीट उसे दिए जाने का प्रस्ताव भी दिया पर सपा इसके लिए राजी नहीं हुई। इसके बाद कांग्रेस ने सभी सीटों से अपनी दावेदारी छोड़ने का मन बना लिया है। गाजियाबाद की बात करें तो लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस की डाली शर्मा चुनाव मैदान में थीं और भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग ने उन्हें 3,36,965 मतों के भारी अंतर से हराया था। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में अतुल गर्ग को 1,37,206 वोट मिले थे और डाली शर्मा को 73,950 वोट ही मिले थे। वहीं अलीगढ़ सीट सपा के हिस्से थी। बात एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी की कि जाये तो वह भी उपचुनाव में लड़ने को तैयार है। पार्टी के अध्यक्ष व मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने बताया कि मझंवा व कटेहरी विधानसभा सीट पर हम अपने चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी लड़ाएगें। उन्होंने कहा कि भले ही भाजपा हो, लेकिन चुनाव चिन्ह निषाद पार्टी का होना चाहिए।

भ्रष्टाचार से कांग्रेस ने सबक नहीं सीखने की ठान ली!

योगेंद्र योगी

कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के कारण देशभर में हुई बदनामी से सत्ता गंवाने के बावजूद सबक नहीं सीखा है। कांग्रेस के केंद्र और ज्यादातर राज्यों से सत्ता बाहर होने का एक प्रमुख कारण भ्रष्टाचार रहा है। इसके बावजूद कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार से दामन नहीं छुड़ा पाएं हैं। कर्नाटक कांग्रेस की सरकार के जमीनों में बंदरबांट इसका नया उदाहरण है। इसके चलते मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष मारी गौड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उल्लेखनीय है कि उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बीएन पार्वती और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ चल रहे भूमि घोटाले की जांच राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही है। सिद्धारमैया और उनकी पत्नी बीएन पार्वती पर मैसूरु के विजयनगर क्षेत्र में 14 प्लॉट आवंटित किए गए प्लॉट को लेकर सवाल उठे थे। सिद्धारमैया की पत्नी ने प्लॉट लौटाने की पेशकश की थी। जिसे वापस लेने पर प्राधिकरण ने सहमति जताई। मुख्यमंत्री के जमीन आंवटन में हेराफेरी की जांच के बीच मल्लिकार्जुन खडगे ने कर्नाटक द्वारा आवंटित जमीन लौटा दी। यह विवाद मार्च 2024 में शुरू हुआ, जब कर्नाटक कांग्रेस सरकार ने राहुल खडगे की अध्यक्षता वाले सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को ज़मीन दी। विचाराधीन भूमि मल्लिकार्जुन खडगे के बेटे राहुल एम खडगे को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा बगलूर में हाई-टेक डिफेंस एंड एयरोस्पेस पार्क के हार्डवेयर क्षेत्र में आवंटित की गई थी। कांग्रेस का शायद ही ऐसा कोई वरिष्ठ नेता होगा जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप और मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। पार्टी में कनिष्ठ से लेकर शीर्ष तक के नेताओं के खिलाफ गंभीर मामले चल रहे हैं। यहां तक कि पार्टी चलाने वालीं पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी भी जमानत पर चल रहे हैं।

भ्रष्टाचार के मामलों को देखें तो दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के बड़े कांग्रेस नेता

सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसी एजेंसियों के निशाने पर हैं। हालांकि कांग्रेस अपने नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार करती रही है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी की मोदी सरकार राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। करोड़ों की एंबुलेंस खरीद में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ए.ए खान, श्वेता मंगल, शफी माथेर और निदेशक एन आर एच एम के विरूद्ध 2013 तक एनआरएचएम के तहत एंबुलेंस खरीदने में हुई धांधली का मामला दर्ज किया गया था। एंबुलेंस खरीदने के लिए जो टेंडर जारी किया गया, उसमें गड़बड़ी की गई थी। इस मामले में 31 जुलाई 2014 को जयपुर के अशोक नगर थाना पुलिस ने जयपुर नगर निगम के पूर्व मेयर पंकज जोशी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। कर्नाटक में कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने का मामला चल रहा है। 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डीके शिवकुमार के 64 ठिकानों पर जबर्दस्त छापेमारी की थी। टैक्स चोरी की शिकायतों पर यह कार्रवाई हुई थी। उस दौरान डीके शिवकुमार व अन्य कांग्रेस नेताओं ने राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। इसी तरह वीरभद्र सिंह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह के खिलाफ भी केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की। सितंबर 2015 में उनकी बेटी की शादी के दिन सीबीआई ने छापेमारी कर खलबली मचा दी थी।

कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इतालवी चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोपों की सीबीआई आदि केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी फंसे हैं। यह मामला अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 36 अरब रुपए के 12 वीआईपी हेलिकॉप्टर खरीदने थे से जुड़ा है। आरोप है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया इस वीआईपी चॉपर खरीद के पीछे अहम भूमिका निभा रही थीं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को पिछली मोदी सरकार में उठाया था, जिसके बाद घमासान मचा था।

नेशनल हेराल्ड केस-2011 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता फंसे हैं। आरोप है कि कांग्रेस के पैसे से 1938 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी खड़ी की गई, जो नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और क़ौमी आवाज़ नामक तीन अखबारों का संचालन करती थी। एक अप्रैल 2008 को सभी अखबार बंद हो गए. इसके बाद कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपये की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। मतलब पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया। इसके बाद 5 लाख रुपये से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया और राहुल की 38-38 फीसदी हिस्सेदारी है। बाद में घालमेल कर यंग इंडियन के कब्जे में एजेएल कंपनी को कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। यानी यंग इंडियन को एक प्रकार से मुफ्त में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी का मालिकाना हक मिल गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर लंदन में 12, ब्रायनस्टन स्क्वायर में एक संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.9 मिलियन पाउंड (17 करोड़ से अधिक) है। इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। इसके अलावा हरियाणा में हुड्डा की कांग्रेस सरकार के दौरान वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील का बड़ा घोटाला उजागर हुआ था।

रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुडग़ांव के मानेसर-शिकोहपुर में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में करीब 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। हुड्डा सरकार ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को इस जमीन पर आवासीय परियोजना विकसित करने की स्वीकृति दी थी। मुश्किल से चार महीने में 700 प्रतिशत से ज्यादा का मुनाफा वाड्रा की कंपनी को होता है, वहीं 2012 में हुड्डा सरकार कॉलोनी बनाने वाले लाइसेंस को डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोपों की फेहरिस्त काफी लंबी है। आश्चर्य की बात यह है कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने कभी भी भ्रष्टाचार को जड़ से उखाडऩे का वादा नहीं किया। यही वजह रही कि कांग्रेस इस मुद्दे पर भाजपा के निशाने पर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी कई भाषणों में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के जमानत पर बाहर होने पर चुटकी भी लेते रहे हैं। संसद के बीते बजट सत्र के दौरान जब कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा था कि भ्रष्टाचार के मामले हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते, तब पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा था- जमानत पर हैं तो एन्जॉय करिए। कांग्रेस को भाजपा नेताओं के ऐसे तीखे व्यंग्य बाणों का निशाना झेलना पड़ा है। इसके बावजूद कांग्रेस ने कभी भी अपनी छवि सुधारने के लिए कोई कठोर कदम उठाए नहीं। यह निश्चित है कि जब तक कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामलों में कठोरता की नीति नहीं अपनाएगी तब तक देश पर राज करने का उसका ख्वाब पूरा नहीं होगा।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्यायः

गतांक से आगे...

इस प्रकार का निरर्गल प्रश्न करने वाले पुरुष को वैदिक-साहित्य से सर्वथा अपरिचित और दो चार ट्रैक्ट बाँच कर वेदालङ्कार का पुछल्ला लगाने वाला ही समझना चाहिए, क्योंकि जब स्वयं वेद में ही विनियोग-ज्ञान की परमावश्यकता बतलाई है और विनियोगरहित मन्त्र का पढ़ना-पढ़ाना व्यर्थ तथा पापप्रद कहा गया है, फिर इससे बढ़ कर अन्य क्या प्रमाण दिया जा सकता है? रहा दयानन्दी भाष्यों में विनियोगों की उपेक्षा का प्रश्न? सो उसमें भी मन्त्रों के पूर्व ऋषि देवता और छन्द आदि का उल्लेख अवश्य मिलता है।

हमारे सामने वैदिक यन्त्रालय (अजमेर) की छपी सभाष्य यजुःसंहिता विद्यमान है, जिसमें प्रत्येक मन्त्र के ऊपर अमुक ऋषि, अमुक देवता और अमुक छन्द साफ लिखा है, जिससे हमारे पूर्व कथन की पर्याप्त पुष्टि हो जाती है; यानी आर्यसमाज की रीति से भी वेदाध्ययन करते समय मन्त्रों से पूर्व ऋषि देवताओं का नाम ही पढ़ना होगा और फिर उनके चरित्र जानने के लिये पुराणों की शरण में ही नतमस्तक होना पड़ेगा।

इसलिए हमारी विनियोग-कल्पना की आधार शिला दयानन्दी समाज की दृष्टि में भी तथैव दृढ़ बनी रहेगी।

हाँ, यह हम मानते हैं कि दयानन्द और उनके अनुगायियों ने विनियोग के चौथे अङ्ग (जिसमें कि अमुक मन्त्र को अमुक अनुष्ठान में बर्तना चाहिए ऐसी शिक्षा दी गई थी-) का सर्वथा बहिष्कार कर डाला है और मनधड़न्त प्रसङ्ग उपस्थित करके मन्त्रों का अर्थ लिखा है!

परन्तु इस उच्छृङ्खलता के कारण उक्त समाज की बदौलत जो वैदिक-साहित्य के अर्थ का अनर्थ हुवा है वह भी किसी से छुपा नहीं है।

क्रमशः...

पिता शुक्राचार्य के शाप से मुक्ति की चाह, ययाति ने अपने पुत्र का यौवन लिया

आशुतोष गर्ग

शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखकर बृहस्पति का पुत्र कच देवलोक लौट आया। उसके जाने के बाद देवयानी दुखी रहने लगी। देवयानी की मित्रता असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से हो गई थी। दोनों अधिकांश समय साथ बिताने लगीं। एक दिन दोनों स्नान कर रही थीं कि हवा चलने से नदी किनारे रखे उनके वस्त्र बिखर गए। दोनों स्नान करके बाहर निकलीं, तो देवयानी ने भूल से शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए।

यह देखकर शर्मिष्ठा ने कहा, 'राजकुमारी के वस्त्र पहन लेने से तुम कोई राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता, मेरे पिता के सेवक हैं, इसलिए तुम भी मेरी सेविका हो।' इस पर दोनों में बहस हो गई और शर्मिष्ठा ने देवयानी को सूखे कुएं में धकेल दिया और महल में लौट आई। इधर, कुएं में फंसी देवयानी सहायता के लिए पुकारने लगी। संयोगवश उसी समय राजा ययाति वहां से गुजर रहे थे। ययाति ने देवयानी की आवाज सुनी, तो उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। दोनों एक-दूसरे पर मोहित हो गए थे। शुक्राचार्य की सहमति से दोनों का विवाह हो गया।

इसी बीच शुक्राचार्य को पता चला कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में गिरा दिया था। उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने वृषपर्वा को संदेश भेजा कि शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनकर ययाति के महल में रहना होगा, अन्यथा वह असुर-गुरु का पद त्याग देंगे। शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित था। इसलिए शर्मिष्ठा ने दासी बनकर रहना स्वीकार कर लिया। एक दिन शर्मिष्ठा का उद्यान में ययाति से सामना हो गया। ययाति शर्मिष्ठा का अनुपम सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गए। परंतु शुक्राचार्य के कोप का भय उन्हें सता रहा था। आखिर दोनों ने चुपचाप गंधर्व विवाह कर लिया।

कुछ दिन बाद देवयानी के दो पुत्र हुए- यदु और तुर्वसु। उधर ययाति से शर्मिष्ठा के भी तीन पुत्र हुए-दुरुह्यु, अनु और पुरु। इन तीनों का रूप-रंग ययाति जैसा ही था, जिसे देखकर देवयानी को संदेह हो गया। उसने पता किया, तो इसकी पुष्टि हो गई कि शर्मिष्ठा के तीनों पुत्रों के पिता भी ययाति ही थे। देवयानी ने इसकी जानकारी पिता शुक्राचार्य को दी। क्रोधित शुक्राचार्य ने ययाति को शाप दे दिया, जिसके फलस्वरूप ययाति तत्काल वृद्ध हो गए। लेकिन ययाति का मन भोग से भरा नहीं था। उन्होंने शुक्राचार्य से शाप वापस लेने की विनती की। शुक्राचार्य ने ययाति से कहा-मेरा शाप वापस नहीं हो सकता। परंतु तुम्हारा कोई भी पुत्र यदि चाहे, तो अपना यौवन तुम्हें देकर बदले में तुम्हारा बुढ़ापा ले सकता है। तब तुम फिर से युवा हो जाओगे।

यह सुनकर ययाति बड़े प्रसन्न हुए। वह अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु के पास गए और उससे यौवन मांगा, लेकिन यदु ने मना कर दिया। इसी प्रकार तुर्वसु, अनु और दुरुह्यु ने भी ययाति के आग्रह को अस्वीकार कर दिया।

अंत में ययाति अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु के पास गए...पुरु ने सहर्ष अपने पिता का अनुरोध स्वीकार करके उन्हें अपना यौवन देकर उनका बुढ़ापा ले लिया। अगले ही क्षण ययाति युवा हो गए और पुरु वृद्ध बन गए। ययाति ने अगले सौ वर्ष तक यौवन का आनंद लिया, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए।

ब्रिक्स : सबके अपने एजेंडे, अपनी प्राथमिकता

केएस तोमर

रूस के कजान में मंगलवार से शुरू हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एजेंडा आर्थिक सहयोग एवं भू-राजनीतिक रणनीति, दोनों के लिहाज से भारत, चीन और रूस के लिए महत्वपूर्ण है। इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का एजेंडा बहुपक्षवाद को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने और सदस्य देशों-ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सतत विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से संबंधित है। इस शिखर सम्मेलन का विषय है- 'न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना', जो सदस्य देशों के नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा।

भारत ब्रिक्स को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार के एक मंच के रूप में देखता है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अधिक न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने वाला ब्रिक्स खेमे का नया विकास बैंक (एनडीबी) पश्चिमी नेतृत्व वाली वित्तीय संस्थाओं को संतुलित करने का कार्य करता है।

ब्रिक्स की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ग्लोबल साउथ (तीसरी दुनिया के विकासोन्मुखी देश, जिन्हें वैश्विक दक्षिण भी कहा जाता है) में अपने प्रभाव का विस्तार करने और पश्चिमी प्रभुत्व वाली वित्तीय प्रणाली पर निर्भरता कम करना चाहता है। अमेरिकी डॉलर को चुनौती देने के लिए चीन व्यापार समझौतों में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग पर जोर देता है। पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहे रूस के लिए ब्रिक्स वैश्विक अलगाव से बचने का एक महत्वपूर्ण गठबंधन है।

भारत भले ही क्वाड जैसे गठबंधनों के जरिये पश्चिम और अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाए

हुए है, लेकिन अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स का उपयोग करता है। भारत का जोर अक्सर बहुपक्षवाद पर रहता है, जो इस पर किसी एक देश के एजेंडे को हावी नहीं होने देता है। चीन के लिए ब्रिक्स एक वैश्विक व्यवस्था बनाने का साधन है, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है।

हालांकि यह समूह में प्रभुत्व का दावा करता है, लेकिन अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी विकासशील देशों के साथ साझेदारी बनाने की भी कोशिश करता है। ब्रिक्स बहुपक्षीय मंचों पर प्रभाव बनाने और अमेरिकी नेतृत्व वाली वैश्विक संरचनाओं का विकल्प प्रदान करने के चीन के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करता है। पश्चिम के साथ बढ़ते तनाव के संदर्भ में ब्रिक्स रूस को अपनी वैश्विक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है और नाटो एवं यूरोपीय संघ जैसे पश्चिमी-प्रभुत्व वाले अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का एक प्रतिपक्ष प्रदान करता है।

भारत का लक्ष्य तकनीकी सहयोग के लिए ब्रिक्स का लाभ उठाना है, खासकर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवा व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। ब्रिक्स सहयोग डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप है। प्रौद्योगिकी में चीन का प्रभुत्व उसे नवाचार के मामले में ब्रिक्स के भीतर एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करता है। रूस ब्रिक्स को ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और रक्षा प्रौद्योगिकी सहित उच्च तकनीक क्षेत्रों में सहयोग के एक मार्ग के रूप में देखता है। प्रतिबंधों के बावजूद रूस परमाणु ऊर्जा जैसी अत्याधुनिक तकनीकों में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है।

ब्रिक्स के भीतर ऊर्जा सुरक्षा भारत की मुख्य प्राथमिकता है। यह ऊर्जा विविधीकरण पर सहयोग के लिए ब्रिक्स की ओर देखता है, विशेष रूप से स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में। सतत विकास पहलों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन शमन भी भारत के एजेंडे में है। प्रमुख ऊर्जा निर्यातक रूस ब्रिक्स के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। ब्रिक्स रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच, विशेष रूप से गैस और तेल जैसे क्षेत्रों में नए बाजारों और ऊर्जा परियोजनाओं की खोज करने की अनुमति देता है।

भारत अपने आतंकवाद विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में ब्रिक्स को देखता है, विशेष रूप से पाकिस्तान से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद को उजागर करने के लिए। यह आतंकवाद के वित्तपोषण, साइबर खतरों और अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए ब्रिक्स सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल का आह्वान करता है।

चीन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स का उपयोग करता है, जिसमें आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि चीन का ध्यान अक्सर अपने व्यापक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहता है। रूस का उद्देश्य ब्रिक्स रक्षा पहलों के माध्यम से सैन्य सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करना और पश्चिमी सैन्य प्रभुत्व का मुकाबला करने जैसे मुद्दों पर संबंधों को मजबूत बनाना है।

भारत ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचे के रूप में देखता है। ब्रिक्स भारत की भागीदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की दावेदारी के लिए समर्थन जुटाने में भी मदद करता है। ब्रिक्स चीन को विकासशील देशों के बीच अपनी नेतृत्वकारी स्थिति बनाने और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में अपने भू-राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने का मौका देता है। रूस ब्रिक्स के जरिये बहुध्रुवीयता को बढ़ावा देने व पश्चिमी वर्चस्व का मुकाबला करने वाले ग्लोबल साउथ में खुद को प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। यह पश्चिमी जगत के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्ते के मद्देनजर ब्रिक्स के जरिये अफ्रीकी व लैटिन अमेरिकी देशों से संबंधों को मजबूत करना चाहता है।

भारत, चीन व रूस के लिए ब्रिक्स उनके आर्थिक, भू-राजनीतिक और रणनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के मंच का काम करता है। हालांकि सभी देश बहु-ध्रुवीयता और वैश्विक शासन में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हैं, लेकिन प्रत्येक देश की ब्रिक्स को लेकर प्राथमिकताएं अलग-अलग हैं। भारत के लिए ब्रिक्स रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने और पूर्व व पश्चिम के बीच संबंधों को संतुलित करने का माध्यम है, चीन के लिए यह वैश्विक प्रभाव के विस्तार का साधन, तो रूस के लिए यह अलगाव का मुकाबला करने और वैकल्पिक वैश्विक गठबंधनों को मजबूत करने का मंच है।

आज का इतिहास

1972 वियतनाम युद्ध-ऑपरेशन लाइनबैकर, अपने ईस्टर के आक्रामक के जवाब में उत्तरी वियतनाम के एक अमेरिकी बमबारी अभियान ने बाद के महीनों को समाप्त कर दिया।

1983 लेबनान में मुसलमान संघर्षताओं द्वारा अमरीकी व फ्रांसीसी अतिग्रहणकारियों के ठिकानों पर शहादत प्रेमी आक्रमणों में 241 अमरीकी और 58 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए।

1983 एक आत्मघाती हमलावर ने एक ट्रक को विस्फोटकों से भरा बनाया था, जो बेरूत में अमेरिकी समुद्री बैरक में था, जिससे 241 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई।

1983 लेबनानी गृह युद्ध-आत्मघाती हमलावरों ने बेरुत में दो बैरकों को नष्ट कर दिया, जिसमें 241 अमेरिकी सैनिक और अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना के 58 फ्रांसीसी पैराट्रूपर्स मारे गए।

1989 हंगरी सोवियत संघ से 33 वर्षों के बाद आजाद होकर एक स्वतंत्र गणराज्य बना।

1989 फिलिप्स 66 ह्यूस्टन केमिकल कॉम्प्लेक्स में बड़े पैमाने पर विस्फोट और आग लगी, जिससे 23 कर्मचारी मारे गए और 314 अन्य घायल हो गए।

1993 ट्रबल-ए अनंतिम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के वफादारी के अर्धसैनिक नेताओं की बैठक की कोशिश नाकाम रही, जिसमें एक अपराधी, एक यूडीए सदस्य और आठ नागरिक मारे गए।

1998 जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपने पहले बैंक का राष्ट्रीयकरण किया।

2001 नासा के मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह की परिक्रमा शुरू की।

2002 चेचन अलगाववादियों ने मॉस्को में लगभग 700 संरक्षक और कलाकारों को बंधक बनाकर एक भीड़ भरे थिएटर को जब्त कर लिया।

2004 जापान में आए भूकंप ने 85 हजार लोगों को बेघर कर दिया।

2007 अंतरिक्ष यान डिस्कवरी को उतारने में सफल रहा। यह एसटीएस -120 चालक दल को ले जा रहा था जो एक असेंबली मिशन पर था।

2009 अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ एक सार्वभौमिक मोबाइल फोन चार्जर को मंजूरी देता है। यह किसी भी मोबाइल हैंडसेट के साथ काम कर सकता है।

2010 यूएस के मौद्रिक सहजता को जर्मन अर्थव्यवस्था मंत्री, रेनर ब्रूडरले द्वारा यूएसडी विनिमय दर में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है।

2011 तुर्की के वान प्रांत में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। जिसमें 582 लोगों की मौत हुई और हजारों घायल हुए।

आखिर कब तक थमेंगे जम्मू-कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले?

कमलेश पांडे

लीजिए, जम्मू-कश्मीर में एक और आतंकवादी हमला हो गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग मारे गए। यह नृशंस वारदात किसकी शह पर हुई और किसकी नीतिगत लापरवाही से हुई, यह पुनः विमर्श का विषय है! क्योंकि हमारे देश में ऐसी घटनाएं आए दिन की बात हो चली हैं और राष्ट्र के किसी न किसी हिस्से में घटित होती रहती हैं। आखिर इस घटना के क्या मायने हैं, इस पर विचार करने से पहले एक सुलगता हुआ सवाल मेरे मनमस्तिष्क में कौंध रहा है कि आखिरकार खूनी होते जा रहे लोकतंत्र और इसको संरक्षित करने वाले संवैधानिक तंत्र के पास ऐसी वहशी वारदातों को रोकने के लिए अबतक कोई स्थायी मूलमंत्र क्यों नहीं मिला है?

आखिर कब तक ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं के खात्मे होंगे और इसे प्रोत्साहित करने वाले लोगों और उन्हें रोकने में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई कबतक सुनिश्चित की जाएगी, ताकि ऐसी वारदातों पर पूर्ण विराम लग सके! यदि नहीं, तो क्यों नहीं? आम जनता को जवाब चाहिए। क्योंकि इस बद से बदतर स्थिति के लिए हमारी राजनीति और उसके इशारे पर थिरकने वाला प्रशासन भी कहीं न कहीं जिम्मेदार अवश्य है। बस इसके न्यायसंगत पड़ताल की जरूरत है, जो बीते कई दशकों से नहीं हो पा रही है!

उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकियों ने एक और कायराना हमला करते हुए 7 मेहनतकश लोगों की उस वक्त जान ले ली, जब वो खाना खाने के लिए मेस में बैठे हुए थे। इस आतंकी वारदात में मरने वालों में एक स्थानीय डॉक्टर और टनल निर्माण में लगे 6 कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनमें से 5 लोग बाहरी राज्यों से थे। उनमें 2 अधिकारी वर्ग के और 3 श्रमिक वर्ग के थे। वहीं, इस नृशंस हमले में 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह हमला सोनमर्ग इलाके में हुआ और घटना के बाद सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में हुए आतंकी हमले में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। यह हमला रात करीब 8:30 बजे हुआ, जब सभी कर्मचारी खाना खाने के लिए मेस में एकत्र हुए थे। चश्मदीदों के मुताबिक, जब कर्मचारी मेस में भोजन कर रहे थे, तभी 3 आतंकी वहां पहुंचे और अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, आतंकी हमला करके वहां से फरार हो गए। इस गोलीबारी में दो वाहन भी आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गए। खबरों के अनुसार, इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' ने ली है। जिसकी अविलंब कमर तोड़ देनी चाहिए।

मसलन, प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि जिन श्रमिकों पर हमला हुआ, वे जेड मोड़ सुरंग परियोजना में काम कर रहे थे, जो गगनगीर घाटी को सोनमर्ग से जोड़ने वाली एक सुरंग है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश की एप्को नामक कंपनी द्वारा किया जा रहा है और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके चलते वहां तेजी से काम चल रहा था। सवाल है कि जब धारा 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है और नेशनल कांफ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला ने घाटी में सरकार बनाई है, तब यह बड़ा सवाल है कि आखिर में आतंकियों के असल निशाने पर क्या था? क्योंकि नई सरकार बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में यह पहली आतंकी वारदात हुई है। वहीं, दूसरा सवाल यह है कि क्या आतंकियों के निशाने पर घाटी के विकास कार्यों को रोकना है? यदि ऐसा है तो यह बेहद खौफनाक है। मेरा स्पष्ट मानना है कि घाटी के विकास को परवान चढ़ा रहे मजदूरों को निशाना बनाकर आतंकियों ने बड़ी कायरता और मूर्खता का परिचय दिया है।

सवाल है कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब विकास की परियोजना पर आतंकियों ने सीधे हमला किया है। जिस टनल के लिए यह मजदूर काम कर रहे थे वो भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक है। इस साल कश्मीर में टीआरएफ का ये पहला बड़ा हमला है। इससे पहले इस साल जम्मू में इस संगठन

ने आतंकी हमले को अंजाम दिया। भले ही केंद्रीय गृह सचिव ने इस आतंकी हमले की जानकारी जम्मू कश्मीर डीजीपी से ली और आतंकियों के खिलाफ चल रहे काउंटर ऑपरेशन का भी ब्योरा लिया।

जानकारों का कहना है कि इस साल जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए हैं, वह जम्मू में हुए हैं। लेकिन यह पहली बार है जब कश्मीर में इस साल इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। वहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि स्थानीय (लोकल) और बाहरी (नॉन लोकल) दोनों को टारगेट किया गया है। इससे साफ है कि विकास परियोजनाओं में शामिल लोगों के हौसले को पस्त करने की खौफनाक रणनीति अब आतंकी संगठन भी अपना रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। क्योंकि गांदरबल में जिस टनल के पास यह आतंकी हमला हुआ है, वह आल वेदर रोड है, जिसका निर्माण पिछले कुछ सालों से चल रहा है। यह रोड़ सीधे गांदेरबल से सोनमर्ग और वहां से लेह को कनेक्ट करता है।

एक सुलगता हुआ सवाल यह भी है कि जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार के गठन के महज चार दिनों के बाद ही आतंकवादियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ही विधानसभा क्षेत्र गांदरबल में इतना बड़ा आतंकी हमला क्यों बोला है और इसके जरिए आतंकियों ने क्या संदेश देने की जुर्रत की है। क्योंकि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे के ऐलान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार गठन के मात्र चार दिनों के अंदर आतंकियों ने गांदरबल में आतंकी हमला बोला है। जहां उन्होंने गुंड इलाके में सुरंग के निर्माण पर काम कर रही एक निजी कंपनी के लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई।

दरअसल, यह आतंकी हमला सियासी रूप से भी काफी अहम है। क्योंकि जिस इलाके में यह हमला हुआ है, वह सीएम उमर अब्दुल्ला के विधानसभा क्षेत्र गांदरबल के अधीन आता है और यहां से उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने बहुमत हासिल कर सरकार का गठन किया है। क्या 370 की बहाली पर चुप्पी साधकर और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाए जानें की सीएम उमर की रणनीति से आतंकवादी नाखुश हैं, क्योंकि जम्मूकश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के उमर कैबिनेट के प्रस्ताव को अब एलजी की मंजूरी का इंतजार है, जो देर-सबेर मिल ही जाएगी।

समझा जा रहा है कि चूंकि जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन के बाद उमर अब्दुल्ला लगातार जम्मू-कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं। उन्होंने लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का वादा किया है। वो जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। साथ ही वह कश्मीर से विस्थापित हुए पंडितों की बात कर रहे हैं। इसलिए आतंकी आका उनकी इस नई चाल से परेशान हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार के गठन के बाद कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव भी पारित किया है और उसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी भी दे दी है। इस तरह से पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब इस पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है और लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन विधेयक लाकर इसको अमलीजामा पहनाना बाकी है। केंद्र सरकार पहले ही पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कह चुकी है।

वहीं, उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर में शांति-अमल और विकास की बात कर रहे हैं, जिससे आतंकी बखौलाए हुए हैं। पहले जिस तरह से जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए और लोगों ने बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है, और अब सरकार भी बन गई है, इससे आर्तकियों के मंसूबे ध्वस्त होते दिख रहे हैं और आतंकी इसी बौखलाहट में ताजा हमला किया है। उनकी मंशा साफ है कि वे सिर्फ दहशत पैदा करना चाहते हैं। इसलिए इस हमले की सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि वह पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

समझा जा रहा है कि दूसरे राज्यों से आकर काम करने वाले, कश्मीरी पंडित और गैर मुस्लिम, सरकारी कर्मचारी और सेना के अधिकारी और गैर मुस्लिम आतंकियों के निशाने पर हैं और वे टारगेट किलिंग कर दहशत फैलाना चाहते हैं। अपनी इसी फितरत से आतंकी लगातार जम्मू-कश्मीर में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनकर लोगों को मार रहे हैं।

इससे पहले भी 16 अक्टूबर को शोपियां में एक युवक को आतंकियों ने गोली मार दी थी। वो लगातार गैर-कश्मीरी को निशाना बना रहे हैं। गत 22 अक्टूबर 2023 को आतंकियों ने राजौरी में एक घर पर फायरिंग कर 40 साल के मोहम्मद रज्जाक की हत्या कर दी थी। मृतक कुंडा टोपे शाहदरा शरीफ का निवासी था। मोहम्मद रज्जाक का भाई सेना में काम करता है। 19 साल पहले आतंकियों ने रज्जाक के पिता की हत्या कर दी थी। वे वेलफेयर डिपार्टमेंट में कार्यरत थे और रज्जाक को पिता की जगह नौकरी मिली थी।

इसी तरह से आतंकियों ने अप्रैल 24 में ही शोपियां जिले के पदपावन में गैर कश्मीरी ड्राइवर परमजीत सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी थी। दिल्ली के रहने वाले परमजीत पर आतंकियों ने उस समय हमला बोला था, जब वह ड्यूटी पर तैनात थे। अप्रैल 24 में ही आतंकियों ने बिहार के एक प्रवासी शंकर शाह की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इससे पहले फरवरी 24 में पंजाब के अमृतसर के दो युवकों अमृत पाल (31 वर्ष) और रोहित मसीह (25 वर्ष) को एके-47 राइफल से भून डाला था। हब्बा कदल इलाके में इस घटना को अंजाम दिया था।

यही वजह है कि इन आतंकी हमलों की चौतरफा निंदा भी हो रही है। खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस घटना की निंदा की है। वहीं, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल जिले में प्रवासी मजदूरों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग के गगनगीर में निर्दोष मजदूरों पर हुए भयानक आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं, जो एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना में लगे हुए थे। उन्होंने शहीद मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायलों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आतंकी हमले की निंदा की और कहा कि जम्मू-कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ नृशंस आतंकी हमला कायरतापूर्ण घृणित कृत्य है। जिसमें शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। वहीं, जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने हमले पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसी घटनाएं माहौल को खराब करेंगी। उन्होंने सरकार से निर्दोष मजदूरों पर इस तरह के क्रूर हमलों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह भी किया।

इसलिए मेरा विचार है कि आतंकी, नक्सली और आपराधिक वारदातों में मारे जाने वाले शांतिप्रिय और मेहनतकश लोगों को भी अमर शहीद का दर्जा दिया जाए। क्योंकि हमारी संवैधानिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक नीतियों की सामूहिक विफलता/खामियों से उतपन्न अराजक परिस्थितियों के ही शिकार तो लोग हो रहे हैं, जिनके परिजनों को भी अमर शहीदों की तरह सभी सुविधाएं प्राप्त करने का हक है। चूंकि ये सभी भारतीय नागरिक हैं, इसलिए उन्हें ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। बेहतर होगा कि इसके लिए देश के तमाम धर्मस्थलों और सरकारी मुलाजिमों पर अधिशेष करारोपण किया जाए और इसके वास्ते एक स्थायी कोष बनाया जाए। धर्मस्थलों को मिल रहे अकूत दान का उपयोग ऐसे ही नैतिक कार्य के लिए किया जाए, तो यह अच्छा है, ताकि जनचेतना को एक नया विस्तार मिले और जिम्मेदारी भाव पनपे। क्योंकि लोगों में मनोमस्तिष्क में निरन्तर यह सवाल कौंध रहा है कि आखिर कबतक थमेंगे जम्मू-कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले और यदि नहीं तो फिर सख्त उपाय क्यों नहीं अपनाते सरकारी मुलाजिम और उनके आका राजनेतागण? जवाब दीजिए!

यूपी में भाजपा हिंदुत्व एवं राष्ट्रवाद के सहारे

अजय कुमार

इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में भले ही संविधान,आरक्षण और जातीय समीकरण साध कर बीजेपी की हिन्दुत्व की राह में रोड़े बिछा दिये थे, लेकिन कहते हैं कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है और हाल ही में सम्पन्न हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधान सभा चुनाव में बीजेपी के हिन्दुत्व ने एक बार फिर हुंकार भरी और कांग्रेस के हरियाणा में सरकार बनाने के सपने चूर-चूर हो गये। इसी से उत्साहित बीजेपी अब यूपी के उप चुनाव में भी हिन्दुत्व की पिच पर बैटिंग करने का मन बना चुकी है। जातीय समीकरण को साधने के लिए भाजपा फिर हिंदुत्व के एजेंडे का इस्तेमाल करेगी। कहा जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव का फायदा भाजपा यूपी के उपचुनाव में भी उठाना चाहती है। पार्टी का भी मानना है कि हिंदुत्व के फार्मूले से जातीय समीकरण साधने में उसे मदद मिलेगी। भाजपा का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व यूपी की नौ विधानसभा सीटों के लिए नवंबर में होने वाले उपचुनाव में हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद के फार्मूले का परीक्षण करेगी।

लोकसभा चुनाव में यूपी में मनमाफिक नतीजे नहीं आने से दुखी बीजेपी को अगर हिंदुत्व के सहारे उप चुनाव में सफलता मिलती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसी आधार पर पार्टी का आलाकमान रणनीति बनाई जायेगा। दरअसल, हरियाणा में लगातार तीसरी बार और 2014 व 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाकर भाजपा ने सारे कयासों को झुठला दिया है। वहीं, जम्मू-कश्मीर में सरकार बनाने का करिश्मा भाजपा भले ही नहीं कर पाई हो, लेकिन वहां मिले सबसे ज्यादा वोटों ने पार्टी में नई उम्मीद जगाई है।

लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में आए नतीजों को कांग्रेस ने भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति से विदाई के तौर पर प्रचारित किया। अब हरियाणा और जम्मू-कश्मीर ने इसे एक तरह से खारिज कर दिया है। साफ है कि अब भाजपा यूपी के उपचुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देगी। इसका असर प्रदेश में दिखने भी लगा है। हालांकि, भाजपा के एजेंडे की काट को लेकर कांग्रेस और सपा ने भी तैयारी शुरू कर दी है।

बता दें हरियाण की तरह जम्मू-कश्मीर में भी ज्यादातर हिंदू भाजपा के पक्ष में गोलबंद दिखे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, हिंदू लामबंदी जिस तरह जातीय गोलबंदी पर भारी पड़ती दिखी है, वह यह बताने को पर्याप्त है कि बंटोगे तो कटोगे के नारे ने नतीजों पर असर डाला है। जाहिर है कि भाजपा इसे और धार देगी ताकि यूपी में 2014 से लेकर 2022 जैसे समीकरणों को फिर मजबूत किया जा सके।

आतंकवाद का प्रायोजक है कनाडा

राम माधव

पिछले सितंबर में, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सनसनीखेज आरोप लगाए थे कि उनकी सरकार ने कनाडा के कट्टरपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों की संलिप्तता के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की थी। निज्जर उन भारतीय खालिस्तानी कार्यकर्त्ताओं में से एक था, जो 1980 के दशक में पंजाब में चरमपंथ पर सरकार की कार्रवाई के मद्देनजर देश छोड़कर भाग गया था। निज्जर की हत्या 18 जून, 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में एक गुरुद्वारे के परिसर में की गई थी। रॉयल कैनेडियन माऊंटेड पुलिस (आर.सी.एम.पी.) ने अपराध में शामिल होने के आरोप में 4 सिख युवकों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पिछले एक साल में मामले में बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है क्योंकि आर.सी.एम.पी.अदालतों के समक्ष कोई सबूत पेश करने में विफल रही है। हालांकि, आर.सी.एम.पी. अधिकारियों और खुद ट्रूडो ने एक बार फिर भारत की संलिप्तता के बारे में सनसनीखेज दावे करना शुरू कर दिया, इस बार उन्होंने भारत के वरिष्ठ अधिकारियों पर उंगली उठाई।

पिछले हफ्ते वाशिंगटन पोस्ट में एक विस्तृत रिपोर्ट में मोदी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का नाम इस घटना में सीधे तौर पर शामिल होने के बारे में बताया गया।

यह स्पष्ट है कि ट्रूडो सरकार ने भारत सरकार के बड़े नामों को इस संदिग्ध विवाद में घसीटकर एक अराजनयिक, अगर अशोभनीय नहीं तो अशिष्ट रास्ता चुना। कई लोगों का अनुमान है कि यह उनकी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ट्रूडो सरकार पिछले 9 सालों से सत्ता में है और आज बहुत अलोकप्रिय है। कनाडा की अर्थव्यवस्था बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कनाडाई मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रूडो की पार्टी जनमत सर्वेक्षणों में कंजर्वेटिव से 10 प्रतिशत से अधिक मतों से पीछे है।

भारत पर 'कनाडाई लोगों के जीवन' को खतरे में डालने का आरोप लगाने में लापरवाही बरतने का विकल्प चुनकर,ट्रूडो ने कूटनीतिक सीमा लांघ दी है। अब जब तलवारें खींची जा चुकी हैं, तो भारत को आगे आकर बैल को सींग से पकडना़ चाहिए।

जब पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की बात आती है, तो हम सभी मंचों पर, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से, इस्लामी आतंकवाद को प्रायोजित करने, उसे पनाह देने और निर्यात करने में उनकी संदिग्ध भूमिका को उजागर करने में मुखर रहे हैं। लेकिन, किसी तरह, हम पश्चिमी शक्तियों के बारे में ऐसी ही बातें कहने से हिचकिचाते हैं क्योंकि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों जैसे उनके गलत आदर्शवादी बयानों के छद्मवेश से भयभीत हैं। जबकि दुनिया चुपचाप देखती रही, पिछले कुछ दशकों में कनाडा आतंकवाद के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया। पाकिस्तान पर इस्लामी आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप है, जबकि कनाडा दशकों से न केवल इस्लामवादियों को बल्कि कई अन्य लोगों को पनाह दे रहा है। दुनिया के लगभग सभी प्रमुख आतंकवादी संगठनों के गुर्गे दशकों से कनाडा के शहरों से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं।

कथित तौर पर आर्मेनियाई आतंकवादी 1980 के दशक में आए और कनाडा को अपना अपतटीय ठिकाना बना लिया। खालिस्तानियों ने देश में प्रवेश किया और 1985 में एयर इंडिया की उड़ान 182 को बीच हवा में उड़ाने जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त रहे। तमिल टाइगर्स 1980 के दशक के अंत में आए। इसके बाद मध्य पूर्व के आतंकवादी समूह जैसे हमास, हिजबुल्लाह और अन्य फिलिस्तीनी संगठन आए।

महाराष्ट्र में होगी असली-नकली की लड़ाई

गंगाधर ढोबले

महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक हलचल और तेज हो चुकी है। छोटे-मोटे कोई 16 दल मैदान में हैं। इनमें से 6 प्रमुख दल दो गठबंधनों में बंटे हैं, जबकि बाकी 10 छोटे दलों का अपना अलग गठबंधन है। इसे तीसरी आघाड़ी कहा जाता है। इसमें से 7 तो दो बड़े गठबंधनों के साथ हो गए हैं, जबकि बचे 3 ने अपना अलग कुनबा बनाया है, जिसे परिवर्तन महाशक्ति आघाड़ी नाम दिया गया है। चौथा कुनबा भी है, जिसका नाम है वंचित आघाड़ी। भीमराव आंबेडकर के पोते प्रकाश इसके नेता हैं। उन्होंने एआईएमआईएम के ओवैसी के साथ हाथ मिलाया है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महायुति की ओर झुकती नजर आ रही है।

इनमें से प्रमुख दो ही गठबंधन हैं, महायुति और महाविकास आघाड़ी। महायुति का नेतृत्व भाजपा के पास है, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। विभाजित शिवसेना और एनसीपी के गुट इनके घटक दल हैं। इन दलों और उनके नेताओं के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। असली शिवसेना किसकी है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की या उद्धव ठाकरे की, या असली एनसीपी अजित पवार की या शरद पवार की, यह भी साबित होना है। भाजपा के देवेंद्र फडणवीस और कांग्रेस के नाना पटोले के समक्ष भी अपने को साबित करने की चुनौती है। तीसरी या चौथी आघाड़ी के समक्ष कोई चुनौती नहीं, उन्हें तो हाजिरी लगाने के लिए चुनाव लड़ना है। कुल वोटिंग में उन्हें एक से 1.5% वोट ही मिलते रहे हैं।

भाजपा के कोटे में लगभग 150 सीटें आ सकती हैं। पार्टी ने शत प्रतिशत जीत का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब कि इस चुनाव में अधिकाधिक सीटें जीतना और 2029 में अपने बलबूते सरकार बनाने का लक्ष्य। इससे शिवसेना का शिंदे गुट और एनसीपी का अजित पवार गुट चौकन्ना हो गया है। भाजपा

के लिए भी ये दोनों गुट बोझ बनते लग रहे हैं। अजित पवार को लेकर संघ के लोग पहले से नाराज हैं।

हरियाणा में भाजपा-संघ के विशाल नेटवर्क ने हारती हुई बाजी पलट दी थी। वोटर्स तक सीधी पहुंच के लिए ऐसा ही नेटवर्क महाराष्ट्र में भी तैयार है। संघ ने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी अतुल लिमये को जिम्मेदारी सौंपी है। अंचल से लेकर जिला, शहर और ग्राम स्तर तक उनकी बैठकें जारी हैं।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को सत्ता में होने का लाभ मिलेगा। वह लगभग 70 सीटों पर लड़ सकती है। मंत्रिमंडल की पिछली दो-तीन बैठकों में शिंदे ने जिस गति से फैसले लिए, उससे उनकी छवि चमक चुकी है। अंतिम बैठक में 10 मिनट में ही अजित पवार के उठकर चले जाने से साफ हो गया है कि उनकी कम चलती है। इस बैठक में 150 मिनट में रेवड़ियां बांटने वाले 50 से अधिक फैसलों से लोग चौंक गए। लाड़की बहीण (लाडली बहना) योजना, छोटे किसानों को मुफ्त बिजली, साल में तीन मुफ्त रसोई सिलिंडर, युवकों को अप्रेंटिस सहायता, लड़कियों को छात्रवृत्ति, मुंबई के पांच टोल नाकों पर टोल छूट वगैरह ऐसी रेवड़ियां हैं, जिन पर राज्य का सालाना कोई एक लाख करोड़ रुपये खर्च होगा।

अजित पवार की बगावत से मतदाता खुश नहीं दिखते। संघ ने लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा अजित पवार पर फोड़ा है। महायुति में अब उनका दम घुट रहा है, लेकिन शरद पवार ने उनकी वापसी की राह बंद कर दी है। वह अपने गुट के लिए 55-60 सीटें मांग रहे हैं। इससे कम सीटें मिलीं तो पार्टी में ही फूट पड़ जाएगी। अजित खुद बारामती या शिरूर या अन्य किसी सुरक्षित सीट से लड़ सकते हैं। अजित के लिए अपना वजूद बनाए रखने का यही एक अवसर है।

लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सर्वाधिक 13 सीटें जीती थीं। लेकिन सारा जोश और आत्मविश्वास हरियाणा में हार के साथ धुल गया। पार्टी को घटक दलों के साथ अधिक तालमेल से पेश आना होगा। गुटबाजी से बचना होगा। उसे शरद पवार जैसे परिपक्व दिग्गज के साथ मिलकर दांव-पेच बनाने होंगे। सही उम्मीदवारों का चयन मुख्य मुद्दा होगा।

शिवसेना में फूट के बाद ठाकरे सेना में आई मायूसी अब दूर हो चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसने शिंदे सेना से दो सीटें अधिक जीती हैं। उद्धव खुद महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीएम पद का चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस और शरद पवार ने उनकी मांग ठुकरा दी है। मुंबई, ठाणे, कोंकण में उद्धव सेना का दबदबा है। वहां शिंदे सेना के साथ उनकी सीधी टक्कर हो सकती है। उद्धव का स्वास्थ्य और कार्यकर्ताओं व नेताओं के साथ मेल-मिलाप की कमी उनका कमजोर पक्ष है। आघाड़ी में शरद पवार सबसे अनुभवी, परिपक्व और शानदार रणनीतिकार हैं। वह अपने बलबूते 60 से अधिक सीटें पा सकते हैं। लेकिन, केवल उनके बल पर महाविकास आघाड़ी सत्ता के करीब कितना पहुंच सकती है, यह सवाल है। एनसीपी में फूट पड़ी, तब 41 विधायक अजित पवार अपने साथ ले गए। केवल 12 विधायक ही शरद पवार के साथ बचे थे। उन्होंने फिर से पार्टी संगठित की है। लोकसभा में अजित के मुकाबले उन्हें बहुत अधिक सफलता मिली। इससे अजित गुट के कई लोग अब फिर से शरद पवार के रास्ते पर हैं। उनके पुणे स्थित 'मोदीबाग' बंगले में नेताओं का आना-जाना बढ़ गया है। पाला बदलने के इच्छुक लोगों में अजित गुट, भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं के भी नाम हैं।

महाराष्ट्र-झारखंड के जनादेश का राष्ट्रीय स्तर पर होगा असर?

राजकुमार सिंह

इधर जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में नई सरकार बनी तो उधर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी बिगुल बज गया। हरियाणा की सत्ता भाजपा यानी राजग को मिली, जबकि जम्मू-कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी इंडिया गठबंधन को। पिछली बार हरियाणा और महाराष्ट्र में साथ विधानसभा चुनाव हुए थे। इस बार हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में चुनाव न करवाए जाने पर सवाल भी उठे। वैसे महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पांच जनवरी, 2025 तक। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 81 विधानसभा सीटोंवाले झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में। 23 नवंबर को पता चलेगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिला। दिल्ली के तीन ओर बसा होने तथा अपने हाई प्रोफाइल रियल एस्टेट कारोबार के चलते राष्ट्रीय राजनीति में हरियाणा भी महत्वपूर्ण है। लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तो देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। मुंबई की महानगर पालिका 'बीएमसी' का बजट कई छोटे राज्यों से ज्यादा है इसलिए महाराष्ट्र की सत्ता का बहुआयामी महत्व है। अपार खनिज संपदा के चलते झारखंड राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राज्य है। झारखंड में महाराष्ट्र की तरह सत्ता परिवर्तन तो नहीं हो पाया, लेकिन राजनीतिक उथल-पुथल चलती रही। आदिवासी सीटों पर फोकस और गठबंधन में टिकट बंटवारे में व्यावहारिक रुख से साफ है कि झारखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। भाजपा के आंतरिक सर्वे में झारखंड में चुनावी परिस्थितियां अपेक्षाकृत अनुकूल बताई जाती हैं। ऐसे में 'इंडिया' गठबंधन भी आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में सत्ता गंवाने का जोखिम नहीं लेगा। कहना नहीं होगा कि महाराष्ट्र की तरह झारखंड में भी 'इंडिया' की बड़ी चुनौती आपस में सीट बंटवारा और फिर सही उम्मीदवारों का चयन होगा। बेशक महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ ही देश भर में दो लोकसभा सीटों और 48 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे। इनमें राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली वायनाड सीट भी है, जहां से प्रियंका गांधी अपनी चुनावी पारी का आगाज करने जा रही हैं। इन उपचुनावों के परिणाम का भी अपना महत्व होगा, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के जनादेश का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि चंद महीने बाद दिल्ली और बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं।

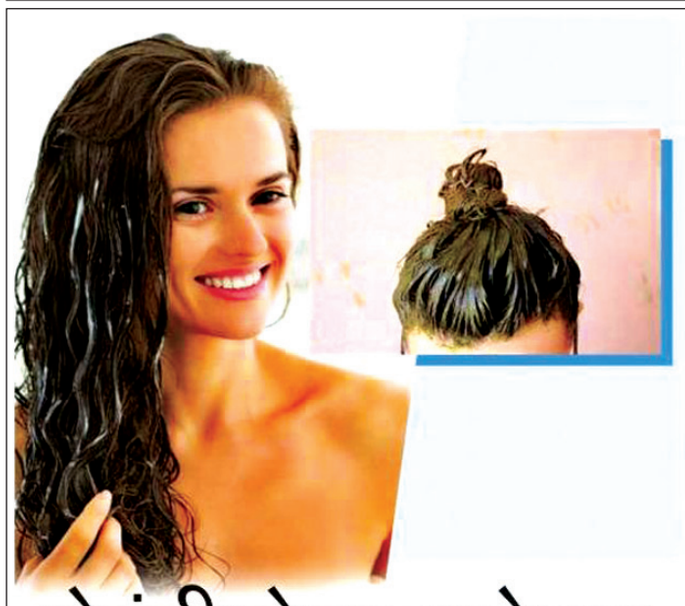

मेहंदी से बाल हो गए हैं ड्राई तो आप भी ट्राई कर सकती हैं ये होममेड हेयर मास्क

आमतौर पर लोग सफेद बालों को कलर करने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं। मेहंदी के इस्तेमाल से बालों को अच्छा कलर तो मिल जाता है और कुछ दिनों के लिए बालों के सफेद दिखने की समस्या भी कम हो जाती है। लेकिन कई बार मेहंदी लगाने के बाद बाल ड्राई होने लगते हैं और ड्राई बाल मुख्य रूप से हेयर फॉल का कारण भी बनते हैं। अक्सर मेहंदी अप्लाई करते समय हम कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बाल ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। जैसे मेहंदी से पहले बालों में तेल न लगाना और रूखे बालों में ही मेहंदी लगाना।

जब हम रूखे बालों में ही मेहंदी का इस्तेमाल करने लगते हैं तो मेहंदी लगाने के बाद बाल और ज्यादा रूखे और बेजान हो जाते हैं। अगर आपके बाल भी मेहंदी के बाद ज्यादा ड्राई हो जाते हैं तो आप इनकी ड्राइनेस कम करने के लिए बालों में कुछ होममेड हेयर मास्क अप्लाई कर सकती हैं। ये हेयर मास्क वैसे तो पूरे तरह से प्राकृतिक हैं और इनका बालों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन बालों में ये हेयर मास्क अप्लाई करने से पहले आप विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें क्योंकि सभी के बालों का प्रकार अलग होता है और किसी भी सामग्री का असर आपके बालों पर अलग तरीके से हो सकता है।

बालों में मेहंदी लगाने के बाद इन बातों का रखें ध्यान

यदि आप बालों में मेहंदी अप्लाई करती हैं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये है कि मेहंदी लगाने से पहले किसी भी ऑयल जैसे जैतून या नारियल के तेल का इस्तेमाल करें।

ब्राउन शुगर और ऑलिव ऑयल हेयर मास्क

ब्राउन शुगर बालों के लिए एक बेहतरीन एक्सफोलिएंट है जो आपके स्कैल्प से उन मृत त्वचा कोशिकाओं और किसी भी बचे हुए अवशेष के निर्माण से छुटकारा पाने में मदद करता है। वहीं जैतून का तेल हमेशा सूखे बालों के इलाज के लिए प्राकृतिक कंडीशनर के रूप में उपयोग किया जाता है। यह बालों को नमी प्रदान करके बालों की ड्राइनेस को कम करने में मदद करता है।

आवश्यक सामग्री

शुगर - 2 बड़े चम्मच
जैतून का तेल- 1 बड़ा चम्मच

हेयर मास्क बनाने और इस्तेमाल का तरीका

- एक बाउल में चीनी और तेल को एक साथ मिलाकर हेयर मास्क तैयार करें।
- इस हेयर मास्क को अपने बालों में ऊपर से नीचे तक लगाएं।
- हेयर मास्क को अपने बालों पर 15-20 मिनट के लिए लगा रहने दें।
- बालों को शॉवर कैप से ढककर रखें।
- 15 -20 मिनट के बाद बालों को अच्छी तरह से शैम्पू करें और शैम्पू के बाद बालों में कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें।

मेहंदी बालों से हटाने के तुरंत बाद शैम्पू न करें बल्कि कम से कम 12 घंटे बाद ही बालों को शैम्पू करें। शैम्पू के बाद आप कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मेहंदी बालों को ड्राई कर सकती है।

बालों में मेहंदी के बाद होममेड हेयर मास्क क्यों जरूरी है

यदि आप मेहंदी से ड्राई हो चुके बालों में होममेड हेयर मास्क अप्लाई करती हैं तो ये 20 मिनट से भी कम समय में आपके बालों को ढेर सारे लाभ प्रदान करने में मदद करता है। हेयर मास्क आपके बालों को मुलायम और हाइड्रेटिंग बनाने के साथ बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देने, बालों में चमक जोड़ने और यहां तक कि बालों के झड़ने को कम करने में भी मदद करते हैं। आइए जानें मेहंदी का बालों में इस्तेमाल करने के बाद आप कौन से हेयर मास्क का इस्तेमाल अपने बालों में कर सकते हैं।

नारियल तेल का हेयर मास्क

नारियल तेल बालों की ड्राईनेस को कम करने में मदद करता है और मेहंदी से ड्राई हो चुके बालों को भी शाइन प्रदान करने में मदद करता है।

आवश्यक सामग्री

शहद - 1 बड़ा चम्मच
नारियल तेल - 1 बड़ा चम्मच

बनाने और इस्तेमाल का तरीका

- एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच नारियल का तेल और 1 बड़ा चम्मच शहद डालकर आपस में अच्छी तरह से मिलाएं।
- मिश्रण को एक बर्तन में निकाल लें और इसे गर्म करें ताकि शहद और नारियल का तेल एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
- मिश्रण को वापस बाउल में डालें और ठंडा होने दें। फिर, अपने बालों पर ऊपर से नीचे तक मास्क लगाएं और अपने पूरे बालों पर पूरी तरह से अप्लाई करें। यदि आपकी जड़ें आमतौर पर काफी ऑयली हैं, तो केवल मध्य लंबाई से नीचे तक मास्क लगाएं।
- बची हुई नमी को बनाए रखने के लिए शॉवर कैप लगाएं।
- 20 मिनट के बाद अपने बालों को गर्म पानी से धो लें और हमेशा की तरह शैम्पू और कंडीशनर करें।
- अगर आपके बाल मेहंदी लगाने के बाद रूखे हो गए हैं तो आपको बालों की ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है। इसके लिए यहां बताए हेयर मास्क अप्लाई करें। लेकिन इन मास्क का इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

वेडिंग गिफ्ट जा रही हैं खरीदने तो इन जरूरी बातों को रखें खास ख्याल

शादियों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में सिर्फ कपड़े-गहने ही नहीं बल्कि गिफ्ट की भी खरीदारी शुरू हो जाती हैं। खासकर अगर शादी घर के किसी सदस्य की हो तो इस बात को सोचना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर गिफ्ट में दूल्हा और दुल्हन को क्या दिया जाए? बता दें कि इंडियन वेडिंग में महंगे तोहफे देने का रिवाज काफी पुराना है, लेकिन अब समय काफी बदल गया है, ऐसे में बजट के साथ-साथ जरूरत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।

वहीं कुछ लोग वेडिंग गिफ्ट खरीदारी में समय अधिक चला जाता है। दरअसल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग गिफ्ट को लेकर काफी कंफ्यूजन रहते हैं, ऐसे में हम पहले डिसाइड कर लें, तो पैसे और समय दोनों को बचाया जा सकता है। इसलिए वेडिंग गिफ्ट की खरीदारी करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।

वेडिंग गिफ्ट सेलेक्शन

वेडिंग गिफ्ट में क्या दें, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। आप इसे बारे में दूल्हा या फिर दुल्हन से सवाल भी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरों से पूछने पर वो अलग से आपको आइडिया दे सकते हैं। इस तरह कंफ्यूजन काफी बढ़ जाता है, इसलिए बेहतर है कि आप खुद तय करें कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को किन चीजों को जरूरत अधिक पड़ती है। उसे ध्यान में रखते हुए गिफ्ट की खरीदारी करें। इसके अलावा गिफ्ट इस उम्मीद से ना दें, आपको वापस मिल सकता है। गिफ्ट अच्छा और जरूरत को ध्यान में रखकर दें।

कैश रजिस्टरी का ऑप्शन चुने

वेडिंग गिफ्ट के तौर पर कैश रजिस्ट्री का ऑप्शन चुन सकती हैं। वेडिंग गिफ्ट की खरीदारी से पहले आप चाहें तो कैश रजिस्ट्री का ऑप्शन चुन सकती हैं। दरअसल, आज कल डेस्टिनेशन का ट्रेंड चल पड़ा है। ऐसे में साथ में गिफ्ट ले जाना काफी ओल्ड फैशन हो सकता है। आप चाहें तो कैश रजिस्ट्री का ऑप्शन चुन सकती हैं। कैश रजिस्ट्री कराने से न्यूली मैरिड कपल अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार चीजें खरीद सकती हैं। वहीं कपल भी चाहें तो इस कैश को आने वाले समय के लिए सेव भी कर सकते हैं।

खरीदारी से पहले बजट सेट करें

वेडिंग गिफ्ट की खरीदारी से पहले बजट तय कर लें। दरअसल, कई बार मार्केट में खरीदने कुछ जाते हैं और खरीदकर कुछ लाते हैं। मार्केट में चीजें की तरह-तरह होती हैं, जिसे लेकर कंफ्यूजन काफी होता है। अगर आप बजट सेट करने से आप कंफ्यूज नहीं होंगे और उतनी ही कीमत में आप गिफ्ट खरीदकर लाएंगे। इस तरह आप फिजूलखर्ची से भी बच सकती हैं।

ऑफलाइन और ऑनलाइन चेक करें

कई बार हम वेडिंग गिफ्ट की खरीदारी आखिरी समय में करते हैं, ऐसे में आप चाहे तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का ऑप्शन चुन सकती हैं। दरअसल, घर की शादी में काफी तैयारी करनी पड़ती है।

ऑफलाइन खरीदारी में काफी समय चला जाता है, ऐसे में आप समय को बचाना चाहती हैं तो ऑनलाइन खरीद सकती हैं। वहीं अगर आप ने तय कर लिया कि आपको दूल्हा और दुल्हन को गिफ्ट में क्या देने वाली हैं तो उसे ऑनलाइन पहले चेक कर लें। इसके बाद समय है तो ऑफलाइन खरीदारी कर सकती हैं।

क्वालिटी जरूर करें चेक

अक्सर ऐसा देखा होगा कि लोग शादी के गिफ्ट के तौर पर एक नहीं कई चीजें देते हैं। हालांकि, जब बाद में उसे चेक करें तो कई चीजें खराब या फिर इस्तेमाल के योग्य नहीं होती। इससे छवि खराब होती है, इसलिए एक साथ कई सारी चीजें तोहफे में देने के बजाय एक ही चीज सेलेक्ट और उसे गिफ्ट करें। कोशिश करें कि खरीदारी करते वक्त वेडिंग गिफ्ट को अच्छी तरह चेक कर लें। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए।

शादियों का सीजन चल रहा है और जिनकी शादी होने वाली है, उन्होंने अभी से इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। शादी की तैयारियां केवल शॉपिंग पर खत्म नहीं होती हैं, बल्कि जल्द न्यूली वेड कपल बनने की तैयारी कर रहे जोड़े अपने रूम को सजाने और संवारने के बारे में भी बातें करते हैं।

ऐसा होना चाहिए न्यूली वेड कपल का बेडरूम

दुल्हन का आगमन हजारों खुशियां लेकर आता है। हिंदू धर्म में तो दुल्हन को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसे में देवी लक्ष्मी का गृह प्रवेश परिवार में सुख और समृद्धि लेकर आए, इसके लिए घर में जुड़ने वाली नई सदस्या का खुश रहना बहुत जरूरी है। किसी को भी सबसे ज्यादा सुकून उसके अपने कमरे में मिलता है, इसलिए न्यूली वेड कपल का कमरा सेट करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासतौर पर वास्तु के हिसाब से न्यूली वेड कपल का कमरा कैसा होना चाहिए, इस पर एस्ट्रोलॉजर एवं वास्तु एक्सपर्ट कहती हैं, 'न्यूली वेड कपल के कमरे की दिशा, रंग और उसमें रखे सामान का वास्तु के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। इससे उनका रिश्ता बेहतर बनता है और परिवार के लिए भी सब कुछ शुभ होता है।'

बेडरूम की दिशा

वास्तु एक साइंस है और 'वे ऑफ आर्किटेक्चर' है। इसमें दिशाओं का विशेष महत्व होता है।' इसलिए वास्तु के हिसाब से न्यूली वेड कपल का कमरा साउथ-ईस्ट दिशा में होना चाहिए और घर की सबसे ऊपर वाली मंजिल में होना चाहिए। हालांकि, कई बार वास्तु के हिसाब से न्यूली वेड कपल का कमरा सही दिशा में नहीं होता है। ऐसे में वास्तु दोष को दूर करने के लिए कमरे में बेड की सेटिंग इस तरह होनी चाहिए कि दुल्हन का सिर साउथ में और पैर नॉर्थ में हो। इस दौरान ध्यान रखें कि पैर एकदम दरवाजे के सामने नहीं होने चाहिए। अगर इस दिशा में सोने की व्यवस्था नहीं हो पा रही हैं तो ईस्ट की ओर सिर किया जा सकता है। लेकिन जब भी आपको कंसीव करना हो तो अपने सोने की जगह को बदल लें।

बेड कैसा होना चाहिए

सोशल डेकोरेशन को भूल कर आपको लकड़ी का ही बेड अपने लिए चुनना चाहिए। 'मेटल में कोल्ड एनर्जी होती होती है और वुड में वॉर्म एनर्जी होती है। न्यूली वेड कपल्स को वॉर्म एनर्जी की जरूरत होती है।' इसके साथ ही, इस बात का ध्यान रखें कि बेड में अगर बॉक्स भी है तो उसमें कोई भी कबाड़ न रखें और न ही कोई धारदार चीज रखें। यहां तक की बेड पर पड़ा गद्दा भी सिंगल होना चाहिए।

कैसा होना चाहिए कमरे में शीशा

शीशा आपका प्रतिबिंब बनाता है। किसी भी चीज को डबल करना और एनर्जी को फैलाना शीशे की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए शीशे का सही दिशा में होना जरूरी है। सोते वक्त शीशे में आप नजर न आएं इसके लिए हमेशा शीशा बेड के बगल में होना चाहिए।

कमरे का डेकोरेशन कैसा होना चाहिए

कमरे के डेकोरेशन में सबसे ज्यादा लोग फोटो फ्रेम्स का इस्तेमाल करते हैं। न्यूली वेड कपल्स को भी अपने कमरे में हमेशा ऐसी तस्वीरें लगानी चाहिए, जो उन्हें खुशी दें। भगवान की तस्वीर कभी न लगाएं, सोलो व्यक्ति की तस्वीर न लगाएं और जंगली जानवरों की तस्वीरें भी न लगाएं। कपल अपनी भी तस्वीर लगा सकते हैं।

कमरे का रंग कैसा होना चाहिए

अपना फेवरेट कलर ही कमरे की दीवारों पर कराएं। हो सके तो कमरे में कहीं न कहीं लाल रंग का इस्तेमाल जरूर करें। क्योंकि यह रंग एनर्जी को बढ़ाता है और कपल के बीच के प्रेम संबंधों को मधुर बनाता है। ज्यादा लाल रंग न इस्तेमाल करें क्योंकि इससे कंसीव करने में दिक्कत आती है और लड़ाई झगड़े भी होते हैं।

घर पर बनाएं मूंग दाल डोसा

साउथ इंडियन खाने का अपना अलग ही मजा है। स्वादिष्ट होने के साथ-साथ दक्षिण भारतीय व्यंजन हेल्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें तेल की मात्रा कम से कम होती है। इडली, डोसा, सांभर, रसम, वड़ा, अप्पम, लेमन राइस जैसे अन्य कई व्यंजनों को देखकर आपके मुंह भी पानी आता होगा? दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनका आनंद सुबह नाश्ते, ब्रंच, लंच, स्नैक्स और डिनर में भी ले सकते हैं।

आज हर शहर में आप साउथ इंडियन फूड का आनंद ले सकते हैं। इतना ही नहीं, घर पर भी इन्हें बनाया जा सकता है। अब बात करें डोसा की, तो आज हम आपके लिए डोसा की रेसिपी लेकर आए हैं, लेकिन यह आम डोसा नहीं, बल्कि मूंग दाल से बनने वाला डोसा है। इसे आप केवल दो मिनट में बना भी सकते हैं।

बनाने का तरीका

- मूंग दाल का डोसा बनाने के लिए पहले जरूरी सामग्री को इकट्ठा कर लें। मूंग दाल को कुछ देर पहले भीगोकर रखें। उसके बाद एक मिक्सी में भीगी हुई मूंग दाल, थोड़ा-सा पानी, अदरक और हरी मिर्च डालकर ग्राइंड कर लें।
- जब बैटर तैयार हो जाए तो उसे एक भगोने में निकाल कर रख लें। अब तैयार बैटर में स्वादानुसार नमक और दो चम्मच चावल का आटा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
- अब एक तवा गर्म करें और उस पर यह बैटर फैला लें। थोड़ी देर सेकने के बाद बैटर के ऊपर हल्का-सा तेल डालें और फिर आलू का मसाला डालने की बजाय उसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर और धनिया डालें।
- इसे कुछ सेकंड सेकने के बाद डोसा फोल्ड करें और एक प्लेट पर निकाल लें। स्वादिष्ट टमाटर और नारियल की चटनी के साथ मूंग दाल के इस डोसे को सर्व करें।
- घर पर मूंग दाल का डोसा बनाना बेहद आसान है। इसे बनाने में आपको केवल दो मिनट लगेंगे। आइए जानें इसकी आसान रेसिपी

सामग्री

1 कप मूंग दाल
1 इंच अदरक
2 चम्मच चावल का आटा,
1 हरी मिर्च
आधा कप पानी,
स्वादानुसार नमक
1 बारीक कटा प्याज
1 बारीक कटा टमाटर
1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया

विधि

- भीगी हुई मूंग दाल को एक मिक्सी में डालें और उसमें अदरक और हरी मिर्च डालकर ग्राइंड करें।
- बैटर को एक भगोने में निकालें और उसमें चावल का आटा और नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें।
- अब एक तवा गर्म करें और उसमें तैयार बैटर फैलाएं। ऊपर से हल्का-सा तेल डालें और कुछ देर सेक लें।
- अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर और धनिया डालें। डोसा को फोल्ड कर एक प्लेट में निकालें और चटनी के साथ सर्व करें।

सिर्फ सेहत ही नहीं, घर चमकाने के काम भी आता है जैतून का तेल

जैतून तेल का इस्तेमाल सेहत और ब्यूटी से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि यह घर की सफाई में भी मददगार है। जी हां, जैतून के तेल से आप घर की साफ-सफाई भी कर सकते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह जैतून के तेल का इस्तेमाल आपके घर की छोटी-छोटी प्रॉब्लम को दूर करता है।

लकड़ी के फर्श को करें साफ

1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1/2 चम्मच व्हाइट विनेगर को मिक्स करके उसे अपनी घर की फर्श को साफ करें। यह आपके फर्श को नए जैसा चमका देगा और इससे फर्श के दाग-धब्बे भी आसानी से साफ हो जाएंगे।

पुराने फर्नीचर को रखें नए जैसा

लकड़ी के फर्नीचर की अलग सही तरीके से देखभाल न की जाए तो वह खराब होने लगते हैं। ऐसे में आप कपड़े पर हल्का-सा जैतून का तेल लगाकर लकड़ी के फर्नीचर को साफ करें। उसके बाद सूखे कपड़े के फर्नीचर साफ करें। इससे आपका पुरानी वुडन फर्नीचर भी नया लगेगा।

बर्तनों को चमकाएं

रसोई में खाना बनाते हुए कई बार बर्तन जल जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले उसपर व्हाइट विनेगर और बेकिंग सोडा डालकर बर्तन को साफ करें। फिर उसपर जैतून का तेल और नमक डालकर स्क्रब की मदद से साफ करें। इससे आपका बर्तन बिल्कुल साफ हो जाएगा।

जूट फर्नीचर की सफाई

जूट के फर्नीचर में गंदगी आसानी से नहीं निकलती और उसकी शाइन खोने लगती है। वैक्यून क्लीनर से सफाई करने के बावजूद भी वह अच्छी तरह साफ नहीं होते। ऐसे में आप कपड़े पर जैतून का तेल लगाकर फर्नीचर की सफाई करें। इससे उसकी धूल-मिट्टी भी आसानी से निकल जाएगा और नया भी लगने लगेगा।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

दो दिवसीय यात्रा के लिए पीएम मोदी रूस रवाना

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंगलवार को रूस के कज़ान की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत इस समूह को अत्यधिक महत्व देता है। अपने प्रस्थान से पहले एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कज़ान के लिए रवाना हो रहा हूं। भारत ब्रिक्स को बहुत महत्व देता है और मैं विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की आशा करता हूँ। मैं वहाँ विभिन्न नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हूँ। पीएमओ के बयान में कहा गया है, जुलाई 2024 में मॉस्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन से आगे बढ़ते हुए, कज़ान की मेरी यात्रा भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। मैं ब्रिक्स के अन्य नेताओं से भी मिलने की उम्मीद कर रहा हूं। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 22-24 अक्टूबर तक रूस की अध्यक्षता में कज़ान में आयोजित किया जा रहा है।

इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर भाजपा का तंज

रांची। झारखंड में सत्ताधारी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर मची रार पर भाजपा ने तंज कसा है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि चाहे झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र, सीटों के पेंच से ज्यादा गठबंधन में कई सियासी खुरपेंच हैं। चाहे अघाड़ी हो या फिर गठबंधन, उनके खानदानी खिलाड़ी की एक ही आकांक्षा है और वो है सत्ता में आना। आज जिस भी गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, उसमें पेंच के अलावा खुरपेंच भी हैं। कांग्रेस की मानसिकता सहयोगियों को साथ लेकर चलने की नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों की कोई अहमियत नहीं है। उन्हें भाजपा और नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। झारखंड भाजपा के प्रभारी प्रतुल शाह देव ने लुईस मरांडी और कुणाल सारंगी के झामुमो में शामिल होने पर कहा कि ये जनता से खारिज नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, जिन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला। भाजपा में करोड़ों कार्यकर्ता हैं और उनमें से कुछ को ही चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है।

जर्मन चांसलर शोल्ज की तीन दिवसीय भारत यात्रा 24 से

नई दिल्ली। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज बृहस्पतिवार से भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वे व्यापार, हरित ऊर्जा, द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। शोल्ज ने पिछले साल दो बार भारत की यात्रा की। वे बीते साल फरवरी में द्विपक्षीय राजकीय यात्रा और सितंबर में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर शोल्ज 25 अक्तूबर को सातवें अंतर सरकारी परामर्श (आईजीसी) की सह-अध्यक्षता करेंगे। आईजीसी परामर्श के दौरान चांसलर शोल्ज के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी मौजूद होंगे। संपूर्ण सरकारी फ्रेमवर्क आईजीसी के तहत दोनों पक्षों के मंत्री अपने-अपने जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में चर्चा करते हैं और विचार-विमर्श के नतीजों पर प्रधानमंत्री और चांसलर को रिपोर्ट करते हैं।

वक्फ विधेयक पर जेपीसी की बैठक में बवाल

नई दिल्ली। वक्फ बोर्ड की बैठक में भाजपा और टीएमसी के सांसदों के बीच झड़प की खबर है। बताया जा रहा कि इस झड़प में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी चोटिल हो गए हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश की निगाह जेपीसी की बैठकों पर लगी हुई हैं। लेकिन जेपीसी की बैठकों में झगड़ा, लड़ाई, बहस और गाली गलौच चल रहा है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन जेपीसी की बैठक में दो सांसदों के बीच जबरदस्त बहस हो गई। हालात काबू में ना किए जाते तो मारपीट की नौबत आ गई थी। जानकारी के अनुसार, बनर्जी ने बैठक के दौरान कथित तौर पर कांच की बोतल तोड़कर फेंकी थी, जिसकी वजह से वह घायल हो गए। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है।

एमवीए सरकार को गिराने के षड्यंत्र का करूंगा खुलासा

मुंबई। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को कहा कि वह जल्द ही अपनी एक किताब लेकर आएंगे जिसमें उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर उनके खिलाफ की गई साजिश का ब्यौरा होगा और उन लोगों को बेनकाब किया जाएगा जिन्होंने पिछली एमवीए सरकार को हटाने के लिए काम किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता देशमुख ने कहा कि उन्होंने 14 महीने की जेल के दौरान डायरी ऑफ होम मिनिस्टर नामक पुस्तक लिखना शुरू किया था। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पुस्तक जल्द ही जारी की जाएगी। इस पुस्तक में यह भी बताया जाएगा कि लंबी अदालती लड़ाई के बाद वे किस तरह जेल से बाहर आए। देशमुख ने कहा कि पुस्तक में यह भी जानकारी मिलेगी कि जब वे महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, तो उनके खिलाफ किसने और कैसे साजिश रची तथा यह भी कि कैसे और किसने तत्कालीन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार को गिराने के लिए काम किया।

देर से ही सही, शी जिनपिंग को आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की बात समझ में आ ही गयी

आसान नहीं था चीनी सैनिकों को पीछे हटाना

नईदिल्ली। लंबे तनाव के बाद आखिरकार भारत और चीन के संबंध सामान्य होते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारत ने घोषणा की है कि भारतीय और चीनी वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त के लिए एक समझौते पर सहमत हुए हैं। इस समझौते को रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में चार वर्षों से अधिक समय से जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पिछले कई हफ्तों तक हुई बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया और यह 2020 में पैदा हुए गतिरोध के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया है कि भारतीय और चीनी सैनिक एक बार फिर उसी तरह से गश्त शुरू कर सकेंगे, जैसे वे सीमा पर टकराव शुरू होने से पहले करते थे और चीन के साथ सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

हम आपको बता दें कि मोदी और जिनपिंग के रूस के काजान शहर में बिक्स शिखर सम्मेलन के इतर मंगलवार या बुधवार को द्विपक्षीय मुलाकात करने की संभावना है। समझा जाता है कि यह समझौता देपसांग और डेमचोक में गश्त की शुरुआत करेगा, क्योंकि दोनों इलाकों में कई मुद्दों को लेकर गतिरोध बरकरार था। हम आपको याद दिला दें कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। यह झड़प पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच हुई सबसे भीषण सैन्य झड़प थी। पिछले कुछ वर्षों में कई दौर की सैन्य और राजनयिक वार्ता के बाद दोनों पक्ष टकराव वाले कई बिंदुओं से पीछे हट गए थे। हालांकि, बातचीत में देपसांग और डेमचोक में गतिरोध दूर नहीं किया जा सका।

हम आपको बता दें कि सोमवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''भारत और चीन के राजनयिक एवं सैन्य वार्ताकार पिछले कई हफ्तों से विभिन्न मंचों पर एक-दूसरे के करीबी संपर्क में रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ''इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप, भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त व्यवस्था पर सहमति बनी है, जिससे 2020 में इन क्षेत्रों में उत्पन्न हुए गतिरोध का समाधान और सैनिकों की वापसी संभव हो सकेगी।'' मिस्री ने कहा, ''हम इस संबंध में आगे के कदम उठाएंगे।''

दूसरी ओर, एनडीटीवी विश्व सम्मेलन के एक सत्र में जयशंकर ने समझौते को अंतिम रूप दिए जाने को एक सकारात्मक घटनाक्रम करार दिया। उन्होंने कहा, हम गश्त के साथ सैन्य वापसी पर एक समझौते पर सहमत हुए, जिसके तहत 2020 की स्थिति बहाल हो गई। हम कह सकते हैं कि चीन के साथ सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा कदम है; यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है और मैं कहूंगा कि यह बहुत ही संयमित और बहुत ही दृढ़ कूटनीति का नतीजा है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने संकेत दिए कि भारत देपसांग और अन्य इलाकों में गश्त करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा, हमारे बीच एक सहमति बनी है, जो न सिर्फ देपसांग में, बल्कि और भी इलाकों में गश्त की अनुमति देगी। मेरी समझ से इस सहमति के जरिये हम उन इलाकों में गश्त करने में सक्षम होंगे, जहां हम 2020 में (गतिरोध से पहले) कर रहे थे। जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्ष गतिरोध खत्म करने के लिए सितंबर 2020 से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ हमें स्पष्ट रूप से जवाबी तैनाती करनी थी, लेकिन साथ-साथ हम बातचीत भी करते रहे। सितंबर 2020 से बातचीत कर रहे हैं, जब मैंने मॉस्को में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की थी।

विदेश मंत्री ने कहा, यह बहुत ही संयमित प्रक्रिया रही है और शायद यह जितना हो सकती थी और होनी चाहिए थी, उससे कहीं अधिक जटिल थी। उन्होंने कहा कि 2020 से पहले एलएसी पर शांति थी और हमें उम्मीद है कि हम उस स्थिति को बहाल कर सकेंगे। जयशंकर ने कहा, यह हमारी प्रमुख चिंता थी, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि अगर आप शांति और स्थिरता में खलल डालते हैं, तो आप संबंधों के आगे बढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वार्ता की कठिन डगर पर जयशंकर ने कहा, आप कह सकते हैं कि कई मौकों पर, लोगों ने लगभग उम्मीदें छोड़ दी थीं।

हम आपको बता दें कि भारत लगातार कहता आ रहा है कि जब तक सीमावर्ती इलाकों में शांति बहाल नहीं होती, तब तक चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। भारत गतिरोध शुरू होने के बाद से हुई सभी वार्ताओं में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) पर देपसांग और डेमचोक से अपने सैनिक हटाने का दबाव डाल रहा है। पिछले महीने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में विवाद का जल्द समाधान तलाशने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की थी। ब्रिक्स देशों के एक सम्मेलन से इतर हुई बातचीत में दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले बाकी बिंदुओं से पूर्ण सैन्य वापसी के लिए तत्काल और दोगुने प्रयास करने पर सहमत हुए थे। बैठक में डोभाल ने वांग से कहा था कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता और एलएसी का सम्मान आवश्यक है।

जम्मू-कश्मीर में सरकार बनते ही बदल गये हैं फारूक और उमर अब्दुल्ला के तेवर

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने के बाद से नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के सुर बदल गये हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अब्दुल्लाओं ने 370 की बहाली कराने को जोरशोर से मुद्दा बनाया लेकिन सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं हुई। वहीं चुनावों के दौरान पाकिस्तान से वार्ता की वकालत करते रहे फारूक अब्दुल्ला अब कह रहे हैं कि जब तक पड़ोसी देश जम्मू-कश्मीर में हत्याएं बंद नहीं करता तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती।

जहां तक उमर अब्दुल्ला की बात है तो आपको बता दें कि चुनावों के दौरान वह कहते रहे थे कि दिल्ली साजिशों में व्यस्त है लेकिन अब वह कह रहे हैं कि वह दिल्ली के साथ काम करना चाहते हैं और दिल्ली को भरोसे में लेकर काम करेंगे। यही नहीं, उनकी कैबिनेट ने जो पहला प्रस्ताव पास किया उसमें अनुच्छेद 370 के बारे में कुछ नहीं कहा गया बल्कि सिर्फ जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग की गयी।

दूसरी ओर, नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर इस्लामाबाद भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहता है तो उसे यहां आतंकवादी घटनाएं रोकनी होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक पड़ोसी देश जम्मू-कश्मीर में हत्याएं बंद नहीं करता, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत नहीं हो सकती। अब्दुल्ला ने रविवार को गांदरबल जिले में एक निर्माण स्थल पर हुए आतंकवादी हमले पर टिप्पणी करते हुए कहा, ''मुझे नहीं पता कि भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, यह केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। यह हमारे लिए एक समस्या है और हम इसे वर्षों से झेल रहे हैं। मैं इसे 30 वर्ष से देख रहा हूं। मैंने उन्हें कई बार कहा है कि वे इसे रोकें लेकिन उनकी सोच ही ऐसी है।'' उन्होंने कहा, ''बातचीत कैसे हो सकती है? आप हमारे निर्दोष लोगों को मारते हैं और फिर बातचीत के लिए कहते हैं। पहले हत्याएं करना बंद करो।''

पूर्व मुख्यमंत्री ने इस हमले को दर्दनाक घटना बताते हुए कहा कि इसमें यहां आजीविका कमाने आए गरीब लोग मारे गए। अब्दुल्ला ने कहा, ''यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। गरीब मजदूर यहां आजीविका के लिए आते हैं ताकि वे अपने परिवारों का पेट भर सकें। इन दरिंदों ने उनकी हत्या कर दी। उनके साथ मारे गए लोगों में हमारा एक चिकित्सक भी था। उसने भी अपनी जान गंवा दी।'' अब्दुल्ला ने कहा कि यदि आतंकवादी सोचते हैं कि वे इस तरह के कृत्यों से जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तानी हुकूमत स्थापित कर लेंगे तो यह उनकी गलतफहमी है।

नेकां अध्यक्ष ने कहा, ''इन दरिंदों को क्या मिलेगा? क्या वे सोचते हैं कि वे यहां पाकिस्तान स्थापित करेंगे? हम कई वर्षों से देख रहे हैं कि वे (आतंकवादी) वहां से आ रहे हैं। हम इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम अपनी मुश्किलों से बाहर आ सकें। मैं पाकिस्तान के शासकों से कहना चाहता हूं कि अगर वे वास्तव में भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं तो उन्हें यह बंद कर देना चाहिए। कश्मीर, पाकिस्तान (का हिस्सा) नहीं बनेगा।'' उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर के लोगों को शांति और सम्मान से रहने देना चाहिए तथा उसे अपने देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

खेल
प्रमुख समाचार

ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों से पहले भारत को बड़ा झटका

नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पदक संभावनाओं को करारा झटका देते हुए मेजबान शहर ग्लासगो ने क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और निशानेबाजी जैसे प्रमुख खेलों को 2026 संस्करण से हटा दिया है। ग्लासगो ने बजट के अनुकूल खेलों को 2026 में होने वाले खेलों के लिए चुना है और इसकी लिस्ट भी बनाई है। बजट को सीमित करने और लॉजिस्टिक्स को व्यवस्थित करने के लिए टेबल टेनिस, स्क्वैश और ट्रायथलॉन को भी हटा दिया गया है। ग्लासगोमें केवल चार स्थान ही पूरे खेलों की मेजबानी करेंगे। 2022 बर्मिंघम संस्करण की तुलना में खेलों में आयोजनों की कुल संख्या नौ कम होगी।

राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें संस्करण की शुरुआत 2026 में 23 जुलाई से होगी और यह दो अगस्त तक चलेगा। 2014 में ग्लासगो में ही राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। 12 साल बाद मेजबान के रूप में ग्लासगो की वापसी कई परेशानियां लेकर आई हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने एक बयान में कहा- खेल कार्यक्रम में एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स (ट्रैक एंड फील्ड), तैराकी और पैरा तैराकी, कलात्मक जिमनास्टिक, ट्रैक साइक्लिंग और पैरा ट्रैक साइक्लिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन और पैरा पावरलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, जूडो, बाउल्स और पैरा बाउल्स, और 3×3 बास्केटबॉल और 3×3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल शामिल होंगे। खेल चार स्थानों पर होंगे - स्कॉट्सटाउन स्टेडियम, टोलक्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर, एमिरेट्स एरेना- जिसमें सर क्रिस होय वेलोड्रोम और स्कॉटिश इवेंट कैंपस (एसईसी) शामिल हैं। एथलीटों और सहायक कर्मचारियों को होटल आवास में रखा जाएगा। यह रोस्टर भारत की पदक संभावनाओं के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले संस्करण में देश के अधिकांश पदक हटाए गए खेलों से आए थे।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स ने 930 अंक लुढ़का निफ्टी 309 अंक टूटा

नईदिल्ली। विदेशी निवेशकों की लगातार जारी बिकवाली के बीच भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई और सभी सेक्टर लाल रंग में बंद हुए। पिछले तीन सप्ताह में भारतीय स्टॉक मार्केट में दर्ज की गई यह एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज लगभग सपाट रहते हुए 81,155.08 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 80,149.53 अंक तक जा गिरा था। हालांकि, अंत में सेंसेक्स 1.15 प्रतिशत या 930.55 अंक की बड़ी गिरावट लेकर 80,220.72 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 1.25 प्रतिशत या 309 अंक की गिरावट के साथ 24,472.10 अंक के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल तीस कंपनियों में से 28 कंपनियों के शेयर मंगलवार को गिरावट में बंद हुए। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर सबसे ज्यादा करीब 4 प्रतिशत की गिरावट लेकर बंद हुआ।

अंबुजा सीमेंट खरीदेगी ओरिएंट सीमेंट की 46.8% हिस्सेदारी

नईदिल्ली। अदाणी ग्रुप के मालिकाना हक वाली सीमेंट कंपनी, अंबुजा सीमेंट्स ने 8,100 करोड़ रुपये के निवेश के साथ चंद्रकांत बिड़ला की सीमेंट कंपनी, ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में 46.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील को ओरिएंट सीमेंट के प्रमोटरों के साथ-साथ कुछ पब्लिक शेयरहोल्डर्स से 395.4 रुपये प्रति शेयर के भाव पर शेयरों की खरीद के माध्यम से पूरा किया जाएगा। चंद्रकांत बिड़ला के स्वामित्व वाली कंपनी का अधिग्रहण, 2030 तक 140 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता हासिल करने के अंबुजा सीमेंट्स के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। इस डील के साथ अंबुजा ने आदित्य बिड़ला ग्रुप की कंपनी अल्ट्राटेक को भी पछाड़ दिया है, जो इस कंपनी को खरीदने की दौड़ में थी। पिछले साल दिसंबर में अदाणी ग्रुप ने सांघी सीमेंट का अधिग्रहण किया था।

फिनटेक कंपनी ने कमाया 928.3 करोड़ रुपये का बंपर मुनाफा

नईदिल्ली। पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 928.3 करोड़ रुपये रहा। कंपनी को वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 290.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। पेटीएम ने अपने वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी देते हुए कहा, पेटीएम की समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन आय सालाना आधार पर 34.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,659.5 करोड़ रुपये रह गई। दूसरी तिमाही में पेटीएम को 928.3 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ (मूल कंपनी के मालिकों को देय लाभ) हुआ। इसमें मनोरंजन टिकटिंग व्यवसाय की बिक्री से हुआ 1,345 करोड़ रुपये का लाभ शामिल है। बयान में कहा गया, ''कंपनी का मानना है कि भुगतान तथा वित्तीय सेवाओं के वितरण पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से लाभदायक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। यह बात भुगतान कारोबार के लिए 981 करोड़ रुपये के राजस्व में परिलक्षित होती है।

डेलॉयट का वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7-7.2% बढ़ने का अनुमान

नईदिल्ली। डेलॉयट इंडिया ने मजबूत सरकारी व्यय तथा उच्च विनिर्माण निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सात से 7.2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है। हालांकि, उसने कहा कि वैश्विक वृद्धि में नरमी से अगले वित्त वर्ष की संभावना प्रभावित होगी। डेलॉयट ने अपने 'अक्टूबर 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था परिदृश्य' में कहा, संपन्न विनिर्माण क्षेत्र, स्थिर तेल कीमतें और चुनाव के बाद संभावित अमेरिकी मौद्रिक सहजता से भारत में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिल सकता है, उत्पादन लागत कम हो सकती है तथा दीर्घकालिक निवेश व रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में सालाना अधार पर 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मौद्रिक नीति में आशा के साथ सावधानी के संकेत

डॉ. आर.के. पटनायक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुछ दिन पहले घोषित मौद्रिक नीति में नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जो अप्रैल 2023 से चली आ रही दर है। ऐसे समय में जब दर में कटौती के लिए तर्क दिया जा सकता है कि रिजर्व बैंक ने खुद कहा है कि मुद्रास्फीति को वापस स्थिर स्थिति में ला दिया गया है, तब यह रेपो दर क्षितिज पर कुछ अनिश्चितताओं को देखते हुए सतर्क दृष्टिकोण का संकेत देती है। इनमें मध्य-पूर्व में बढ़ता संकट एक बड़ा कारक है, जिससे भू-राजनीतिक अस्थिरता तथा ऊर्जा और खाद्य कीमतों के बारे में चिंताएं बढ़ी हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास की टिप्पणियों और बयान से जो तस्वीर सामने आती है, उसमें एक तरफ आशावाद और दूसरी तरफ सावधानी है। यह असंगत मिश्रण हमें बताता है कि आरबीआइ की नजर मुद्रास्फीति पर विशेष रूप से केंद्रित है, हालांकि कुल मिलाकर मुद्रास्फीति की स्थिति संतोषजनक है। कई मायनों में, मुद्रास्फीति पर यह नजर उस ढांचे का उत्सव है, जिसे 'एफआइटी' के संक्षिप्त नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण है। इसके तहत रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के माध्यम से मौद्रिक नीति का संचालन करता है, जिसको निर्देश है कि विकास को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत अंक ऊपर या नीचे के दायरे में चार प्रतिशत पर बनाये रखना चाहिए।

हालिया नीतिगत निर्णय एक ऐसी समिति की ओर से आया है, जिसमें नये बाहरी सदस्य हैं क्योंकि अपने संक्षिप्त इतिहास में तीसरी बार समिति ने कार्यकाल पूरा होने के बाद सदस्यों को बदल दिया है। यह एमपीसी प्रणाली की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाता है।

आरबीआइ अधिनियम, 1934 की धारा 45 जेडबी के तहत 27 जून 2016 को गठित होने के बाद से यह एमपीसी की 51वीं बैठक भी थी। रेपो दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय सर्वसम्मत नहीं था। यह बहुमत से हुआ, जिसमें छह सदस्यों में से एक ने दर में कटौती की मांग की। पर एमपीसी ने सर्वसम्मति से मौद्रिक नीति के रुख को 'समायोजन की वापसी' (जून 2022 से लागू) से 'तटस्थ' रुख में स्थानांतरित करने के लिए मतदान किया। तकनीकी रूप से, 'तटस्थ' रुख न तो विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक उदार रुख को दर्शाता है और न ही मूल्य स्थिरता बनाये रखने के लिए एक सख्त रुख को इंगित करता है। जैसा कि आरबीआइ ने कहा है, तटस्थ रुख मूल्य स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से उभरती व्यापक वैश्विक और घरेलू आर्थिक स्थिति को संबोधित करने के लिए 'अधिक लचीलापन और विकल्प' प्रदान करता है। संक्षेप में, गवर्नर के बयान के साथ देखने पर एमपीसी संकल्प स्पष्ट रूप से निकट अवधि में वृद्धि के साथ सौम्य मुद्रास्फीति दृष्टिकोण के साथ एक मजबूत विकास दृष्टि को सामने लाता है। ग्रामीण मांग (बेहतर कृषि स्थिति से प्रोत्साहित) और शहरी मांग (सेवाओं की बढ़त पर आधारित) बढ़ने के साथ-साथ गैर-खाद्य बैंक ऋण में वृद्धि, बेहतर क्षमता उपयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर में उच्च सरकारी निवेश आदि से विकास की गति को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इन आधारों पर 2024-25 में वास्तविक आर्थिक वृद्धि (मुद्रास्फीति को नहीं जोड़ते हुए) 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके अलावा, 2025-26 की पहली तिमाही में अनुमानित वृद्धि 7.3 प्रतिशत होगी। भले ही मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान 2024-25 के लिए 4.5 प्रतिशत और 2025-26 की पहली तिमाही के लिए 4.3 प्रतिशत पर बना हुआ है, लेकिन अप्रत्याशित मौसम की स्थिति, बिगड़ते भू-राजनीतिक माहौल और वैश्विक वस्तु कीमतों में संभावित वृद्धि के संदर्भ में कुछ जोखिम हैं। यहां कुछ प्रासंगिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, क्या आर्थिक विकास को सरकारी निवेश द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जिससे राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा बढ़े? सरकार को उत्प्रेरक की भूमिका निभानी चाहिए और निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी आनी चाहिए।

युवाओं में सेवा और मानवता की भावना जागृत करना है, जिससे वे समाज की बेहतरी में योगदान दे सकें - राज्यपाल

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका आज भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी दुर्ग द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जूनियर रेडक्रॉस प्रशिक्षण सह सद्भावना शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए राज्यपाल श्री डेका ने छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर रेडक्रॉस मीट 2024 कार्यक्रम के लिए प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने रेडक्रास के इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले युवा स्वयंसेवकों के समर्पण और सेवा भावना को नमन किया जो देश के भविष्य हैं और समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हैं। राज्यपाल ने कहा कि रेडक्रॉस न केवल आप सभी को चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में मदद करने का गुर सिखाता है, बल्कि यह मानवता के प्रति आपकी संवेदनशीलता और सेवा भावना को भी प्रबल करता है। यह प्रशिक्षण शिविर आपको न केवल कौशल प्रदान करेगा, बल्कि जीवन के उन आदर्शों को भी सिखाएगा, जिनसे समाज में शांति, सद्भावना और एकता को बढ़ावा मिलता है। आज, पूरी दुनिया विभिन्न चुनौतियों से जूझ रही है। राज्यपाल ने कहा कि शिविर में न केवल आपातकालीन सहायता, प्राथमिक चिकित्सा और आपदा प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि समाज में मानवता, शांति और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, सामुदायिक विकास, सामाजिक समरसता, और नैतिक मूल्यों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। यह शिविर सभी को एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करेगा।

उन्होंने कहा कि आप यहां से जो भी सीखकर जाएंगे, अपने परिजनों को, मित्रों को भी अवश्य सीखाएं और बताएं ताकि आपात कालीन परिस्थितियों में वे भी अन्य लोगों की सहायता कर सकें। राज्यपाल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और भारतीय रेडक्रॉस समिति दुर्ग को इस सफल आयोजन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

रेडक्रॉस सोसायटी के पांच दिवसीय कार्यक्रम में 33 जिलों से आए छात्र-छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ओवर ऑल बेहतर प्रदर्शन के लिए दुर्ग जिले को प्रथम एवं बालोद जिले को द्वितीय स्थान मिला। नारायणपुर जिले की जूनियर रेडक्रॉस सदस्य कु. नीलिमा मण्डावी व कोरिया जिले के बालक श्री रमेश कुमार को सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप राज्यपाल के हाथों सम्मान प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसायटी के सीईओ एम.के.राउत ने शिविर के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला एवं चेयरमेन अशोक कुमार अग्रवाल ने शिविर के गतिविधियों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध : साय

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रगतिरत् कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत् बजट की राशि 50 से बढ़ाकर 75 करोड़ की

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयाली में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली। प्राधिकरण के सदस्यगणों तथा प्रमुख विभागों के सचिवों के उपस्थित में मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण अंतर्गत् स्वीकृत कार्यो की समीक्षा की और निर्देशित किया कि अप्रारंभ कार्यो को निरस्त कर प्रगतिरत् कार्यो को शीघ्र पूर्ण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के सदस्यों से वन-टू-वन चर्चा कर उनके क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और मांगों की जानकारी लेते हुए प्रस्ताव देने की अपील की। उन्होंने बैठक में सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के माध्यम से निराकरण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने विधायक श्रीमती रेणुका सिंह की मांग पर सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बजट राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने की घोषणा की। उन्होंने मयाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की राशि देने की घोषणा भी की। प्राधिकरण की बैठक संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के समय से ही प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। उन्होंने आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए प्राधिकरण का गठन कर संसाधन उपलब्ध कराए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पांच प्राधिकरण है। हमारी सरकार चाहती है कि बस्तर से लेकर सरगुजा क्षेत्र तक का विकास हो। इसके लिए बजट में राशि नहीं होने पर प्राधिकरण के माध्यम से आवश्यक कार्य कराए जाएंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार चाहती है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गो का विकास हो। प्राधिकरण के माध्यम से इन क्षेत्रों में संसाधन की व्यवस्था कर विकास की गति को और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने पीएम जनमन और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य और आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु बजट का प्रावधान किया है। उनकी इन योजनाओं से राज्य के सभी क्षेत्रों में विकास कार्यो को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि उनकी सरकार ने बजट में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए फोकस किया है। हमारी सरकार बस्तर और सरगुजा संभाग क्षेत्र के विकास के लिए वचनवद्ध होकर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने जशपुर जिले के मयाली में प्राधिकरण की बैठक को लेकर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारी की सरहाना की और कहा कि जशपुर जिले में खनिज संसाधनों का भण्डार होने के साथ ही वन एवं वनोपज की उपलब्धता है। यहॉ के वनोपज, महत्वपूर्ण उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर ग्रामीणों एवं किसानों को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्राधिकरण की बैठक अपने गृह जिले तथा मयाली में करने के पीछे यहॉ के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कहते हुए राजधानी रायपुर से बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि वे यहॉ के उत्पादों को देखे, इसका उपयोग करे और इन्हें बढ़ावा देने के साथ ही जशपुर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा दे। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा बताए गए समस्याओं को निराकरण करने की बात कही। उन्होंने लुण्ड्रा-बतौली क्षेत्र में गन्ना खरीदी केन्द्र को प्रारंभ करने की मांग का परीक्षण करने, विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत पहुंचाने की दिशा में कार्य करने, हाथी से जनहानि रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने, क्षति की राशि को बढ़ाने की दिशा में विचार करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने एकल बत्ती कनेक्शन सहित अन्य लोगों को अधिक बिजली बिल मिलने की शिकायत पर ऊर्जा सचिव श्री रोहित यादव को निर्देशित किया कि बिजली बिल संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर निराकरण कराए। उन्होंने खाद्य विभाग के सचिव को जशपुर जिले के कुछ स्थानों पर राशन की कमी संबंधित शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुनकुरी में जल संसाधन संभाग के संभागीय कार्यालय का लोकार्पण रिमोट का बंटन दबाकर किया। बैठक में उपस्थित उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि सरगुजा और बस्तर क्षेत्र का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। प्राधिकरण अंतर्गत् आज की बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र की विकास की प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्राधिकरण के माध्यम से सरगुजा संभाग के लोगों की जीवन में परिवर्तन लाकर उनके जीवन को सुलभ बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि उन्होंने अपने अधीनस्थ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगरी प्रशासन विकास विभाग बैठक लेकर महत्वपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

कांग्रेस हर वर्ग के हित में काम करने वाला संगठन है: बैज

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के असंगठित मजदूर एवं समस्या निवारण प्रकोष्ठ की बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में

संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने हाल ही में नियुक्त हुए प्रदेश उपाध्यक्षों, महासचिवों और जिलाध्यक्षों को नियुक्ति पत्र सौंपे। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा, कांग्रेस हर वर्ग के हित में काम करने वाला संगठन है। हमें कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना है और भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक ने संगठन की मजबूती के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प जताते हुए कहा कि प्रकोष्ठ को जो भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, उनका पालन स्थानीय संगठनों के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम का मंच संचालन महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने किया। इस दौरान प्रमुख रूप से प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, महामंत्री दीपक मिश्रा, संयुक्त महामंत्री शारिक रईस खान सहित सैंकड़ों पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

दक्षिण से आकाश शर्मा प्रचंड मतो से चुनाव जीतेंगे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा प्रचंड मतो से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस का प्रत्याशी युवा है, उनके साथ व्यापक जनसमर्थन है। वे जुझारू है। इसके विपरीत भाजपा प्रत्याशी पर सांसद रहते हुये निष्क्रियता का तमगा लगा हुआ है। रायपुर की जनता ने सांसद के रूप में सुनील सोनी को अवसर दिया था लेकिन वे जन आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाये। कांग्रेस ने उनके मुकाबले सक्रिय युवा को मौका दिया है। विधायक के रूप में आकाश शर्मा रायपुर दक्षिण की जनता की बेहतर सेवा करेंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि दक्षिण विधानसभा का चुनाव में साय सरकार के 11 माह के कुशासन के खिलाफ जनता मतदान करने को तत्पर है। 11 माह में राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था भाजपा की वायदाखिलाफी, सरकार का कुशासन बड़ा चुनावी मुद्दा होगा। केई सरकार 11 माह के अल्प समय में ही इतनी ज्यादा अलोकप्रिय साबित हो सकती है। इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार है। जनता भाजपा सरकार से ऊब चुकी है, अत: जनमानस भाजपा के खिलाफ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य की आम आदमी भाजपा के राज में अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। राजधानी में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में बस स्टैण्ड में एक महिला के साथ सामूहिक दुराचार हो गया। राजधानी में भाजपा के राज में 4 बार गोली चल गयी, अंतरराष्ट्रीय गैंग पर पैर पसार रहे राजधानी चाकूपुर बन गया, राजधानी में आदमी गाजर मूली की तरह काटे जा रहे, मरीन ड्राईव मर्डर ड्राइव बन गया है।

राज्यपाल रमेन डेका ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और छत्तीसगढ़ के समस्त प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना कीं। इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी, विधायक पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

जशपुर कलेक्टर रवि मित्तल बने जनसंपर्क आयुक्त

रायपुर। राज्य सरकार ने 10 आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। इस फेरबदल की प्रमुख बात ये है कि जनसंपर्क विभाग के आयुक्त मयंक श्रीवास्तव को उनके मूल गृह विभाग में स्थानांतरित करना और जशपुर के कलेक्टर रहे रवि मित्तल को जनसंपर्क आयुक्त के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), संवाद और प्रोजेक्ट डायरेक्टर, चिराग परियोजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपना शामिल है। सोनी से होगा सीधा मुकाबला अब सूरजपुर के कलेक्टर पद पर एस. जयवर्धन की नियुक्ति की गई है, जबकि प्रशांत कुमार ठाकुर को नया एसपी नियुक्त किया गया है। पूर्व एसपी एमआर आहिरे को रायपुर में यातायात पुलिस मुख्यालय में उप पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर स्थानांतरित किया गया है। मंगलवार को एमआर आहिरे ने अपना कार्यभार एडिशनल एसपी संतोष महतो को सौंप दिया । राज्य में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी अधिकारी बदले गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार जन्मेजय महोबे को दिया गया है, जबकि मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी की कलेक्टर तुलिका प्रजापति बनाई गई हैं। इसके साथ ही कई अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गई हैं.

रानू और मीरा को स्पेशल कोर्ट से नहीं मिली राहत

रायपुर। प्रदेश में हुए डीएमएफघोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व आईएएस अधिकारी रानू साहू और मीरा वारियर को आज ईडी ने विशेष कोर्ट में पेश किया। दोनों आरोपियों की 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब रानू साहू और माया वारियर 5 नवंबर तक जेल में रहेगी। बता दें कि रानू साहू जून 2021 से जून 2022 तक कोरबा में कलेक्टर थीं। इसके बाद फरवरी 2023 तक वह रायगढ़ की भी कलेक्टर रहीं। इस दौरान माया वारियर भी कोरबा में पदस्थ थीं। कलेक्टर रानू साहू से करीबी संबंध होने के कारण कोयला घोटाले को लेकर माया वारियर के दफ्तर और घर में ईडी ने छापा मारा था। डीएमएफ की बड़ी राशि आदिवासी विकास विभाग को प्रदान की गई थी, जिसमें घोटाले का आरोप है. इसका प्रमाण मिलने के बाद श्वष्ठ ने माया वारियर को भी गिरफ्तार किया गया है।

टुटेजा कांकेर, ढेबर अंबिकापुर, सूर्यकांत जगदलपुर जेल में किये जाएंगे शिफ्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग के आरोपियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष कोर्ट ने इन मामलों में जेल में बंद सभी आरोपियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। यह निर्णय रायपुर जेल में इन आरोपियों के एक साथ रहने के कारण मिली शिकायतों पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे एक सिंडिकेट चला रहे थे और VIP ट्रीटमेंट का लाभ उठा रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश के बहुचर्चित कोयला, शराब और कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल में बंद आरोपियों के जेल ट्रांसफर का आवेदन आया था, जिसके बाद आरोपियों को अलग-अलग जेल में ट्रांसफर किया गया है। शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को अंबिकापुर, अरुणपति त्रिपाठी को सेंट्रल जेल जगदलपुर, अनिल टुटेजा को सेंट्रल जेल कांकेर, मनोज सोनी को दंतेवाड़ा और सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल में भेजने का आदेश स्पेशल कोर्ट ने पारित किया है। गौरतलब है कि इससे पहले कई बार ऐसा देखने को मिला है कि विचाराधीन बंदी बीमार होने की बात कहकर बाहर अस्पताल नहीं, बल्कि होटल में पाए जाते थे। इस प्रकार की गतिविधियां जेल में भी संचालित हो रही थीं, ऐसी आशंकाएं थीं। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए इन्हें अलग किया गया है।

11 एएसपी का तबादला

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में 11 एडिशनल एसपी की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में विमल कुमार बैस एएसपी विशेष आसूचना शाखा मुख्यालय से सेनानी, 11वीं वाहिनी छसबल जांजगीर। हरीश राठौर एएसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा से सेनानी व्हीआईपी सुरक्षा वाहिनी माना रायपुर भेजा गया है। प्रशांत कतलम उप सेनानी, 8वीं वांहिनी छसबल राजनांदगांव से सेनानी 10वीं वाहिनी छसबल, सूरजपर। नेहा पाण्डेय अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक खैरागढ़ से 8वीं वाहिनी छसबल राजनांदगांव। नीरज चंद्राकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से पुलिस अधीक्षक राज्य इन्वेस्टीगेशन एजेंसी एसआईए पुलिस मुख्यालय रायपुर भेजा गया है। मनीषा रावटे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांकेर से सेनानी 20वीं वाहिनी छसबल परसदा महासमुंद। ओम प्रकाश शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर से विशेष आसूचना शाखा पुलिस मुख्यालय रायपुर। गायत्री सिंह उप सेनानी 3री वाहिनी छसबल अमलेश्वर दुर्ग से सेनानी 7वीं वाहिनी छसबल भिलाई। कमलेश्वर प्रसाद चंदेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सारगंढ-बिलाईगढ़ से सेनानी 17वीं वाहिनी छसबल कबीरधाम। निवेदिता पाल उप सेनानी 4थी वाहिनी छसबल माना से सेनानी 6वीं वाहिनी छसबल रायगढ़। सजीत कुमार सेनानी 10वीं वाहिनी सूरजपुर से पुलिस मुख्यालय रायपुर भेजा गया है।

ग्राम कन्हान से आया महिलाओं का चोर गिरोह, दो हुई गिरफ्तार

रायपुर। दीपावली का त्यौहार आने में कुछ दिन ही शेष है और लोग खरीददारी करने के बाजार में आना - जाना कर रहे है और इसी का फायदा उठाने के लिए नागपुर के ग्राम कन्हान से आई दो महिलाओं को ऑटो चालक और उठाईगिरी की शिकार हुई महिला के सहयोग से पुरानी बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों महिलाओं ने शिव वाटिका, अश्वनीनगर की रहने वाली अनिता देवांगन का पर्स पार कर दिया था जिसमें पांच हजार रुपये थे। शिव वाटिका, अश्वनीनगर निवासी अनिता देवांगन (56) सोमवार की दोपहर 3:30 बजे टिकरापारा गई थीं। वहां से उनकी बहन दुर्गा देवांगन ने उन्हें बूढ़ेश्वर मंदिर तक छोड़ दिया और लौट गईं। बूढ़ेश्वर चौक से अनिता एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर अश्वनीनगर जाने लगीं, जिसमें पहले से दो पुरुष बैठे थे। मंगल होटल के पास दो महिलाएं लाखेनगर जाने का बहाना बनाकर अनिता के करीब बैठ गईं। लेकिन उन्होंने लाखेनगर में उतरने के बजाय अश्वनीनगर के पास उतरने का निर्णय लिया। इसी दौरान, एक अन्य ऑटो चालक ने अनिता को चेतावनी दी कि, मैडम, आप अपना पर्स चेक कर लीजिए, अभी जो महिलाएं ऑटो से उतरी हैं, वे उठाईगीर है। अनिता ने तुरंत अपना बैग खोला और देखा कि पांच हजार रुपये से भरा उनका पर्स गायब था।

कृषि विवि में एग्री कार्नीवाल 2024 में "यूथ कानक्लेव" युवाओं की उत्साहित भागीदारी

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित चार दिवसीय एग्री कार्नीवाल - 2024 "राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी" में प्रथम दिवस आज 22 अक्टूबर, 2024 को "यूथ कानक्लेव" के अंतर्गत जॉब फेयर, अन्तर्राष्ट्रीय एजुकेशन फेयर, स्टार्टअप मीट एवं एकेडेमिया-इन्डस्ट्री मीट का शुभारंभ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम बार आयोजित "कृषि जॉब फेयर" में उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों ने अत्यधिक उत्साह से भागीदारी की। लगभग 2000 विद्यार्थियां ने इस आयोजन में भाग लेकर 20

कंपनियों के माध्यम से जॉब प्राप्ति के लिए चर्चा की एवं अपना बायोडाटा जमा किया। विभिन्न कृषि क्षेत्रों यथा बीज, कृषि रसायन, बायोटेक्नोलॉजी एवं डेयरी की कंपनियों ने इस आयोजन में विद्यार्थियों का साक्षात्कार लेकर 85 विद्यार्थियों को जॉब ऑफर पत्र प्रदान किया। जाब फेयर में विद्यार्थियां को विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा "रिज्यूम" बनाने एवं साक्षात्कार में भाग लेने की तकनीकों का भी मार्गदर्शन प्रदान किया। विभिन्न कंपनियों ने भविष्य में जॉब में चयन हेतु विद्यार्थियों का बायोडाटा लिया।

"इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर" में विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक लगभग 250 विद्यार्थियों ने भी उत्साह से भागीदारी की। इस फेयर में चार अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन कंसल्टेंट एजेंसियों ने इच्छुक विद्यार्थियों को विदेशों में शिक्षा के अवसर, एजुकेशन लोन, स्कालरशिप, वीजा संबंधी जानकारी प्रदान की। भविष्य में विदेश में शिक्षा के लिए इच्छुक विद्यार्थियों को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

"इंडस्ट्री-एकेडेमिक मीट" के अंतर्गत कृषि में अनुसंधान एवं विकास की समस्या समाधान पर 10 कम्पनियों एवं विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के प्राध्यापक एवं वैज्ञानिकगणों का चर्चा सम्पन्न हुई। इसके अंतर्गत अनुसंधान बिन्दूओं को निर्धारण किया गया जिससे भविष्य में कृषि विकास पर आने वाली समस्याओं का सामूहिक प्रयास द्वारा निराकरण किया जा सके।

यूथ कानक्लेव के अंतर्गत "स्व-रोजगार एवं स्टार्टअप" कार्यक्रम में विद्यार्थियों, स्टार्टअप्स, के इच्छुक उद्यमी, इन्क्यूबेटर्स, इन्डस्ट्री के प्रतिनिधिगण ने उत्साह पूर्वक भाग लिया।

कोलोसस आई.एम.यू.एन. -वाय.पी. 2024 में सांस्कृतिक, वाद-विवाद और खेलों का भव्य संगम समापन

रायपुर। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर में 20 अक्टूबर, 2024 को वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम कोलोसस आई.एम.यू.एन. -वाय.पी. 2024 का सफलतापूर्वक भव्य समापन हुआ । इस तीन दिवसीय आयोजन की शुरुआत 18 अक्टूबर को हुई, जिसमें कोलोसस के अंतर्गत सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल प्रतियोगिताओं के साथ-साथ विचारोत्तेजक वाद-विवाद और चर्चाएँ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस और यूथ पार्लियामेंट आई.एम.यू.एन. -वाय.पी. के रूप में आयोजित की गईं। इस वर्ष के फेस्ट में भारत भर के विश्वविद्यालयों से उत्साहपूर्वक भागीदारी देखी गई, जिसने छात्रों को अपनी विविध प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने के

लिए एक मंच प्रदान किया। सांस्कृतिक जीवंतता, बौद्धिक संवाद और एथलेटिक प्रतिस्पर्धा के मेल से कोलोसस आई.एम.यू.एन. -वाय.पी. 2024 ने HNLU की समग्र शैक्षिक अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। समापन समारोह ने न केवल विजेताओं का बल्कि एकता, रचनात्मकता और नेतृत्व की भावना का उत्सव मनाया, जो इस आयोजन के दौरान उभरी। समारोह की शुरुआत HNLU के कुलपति प्रो. (डॉ.) वी.सी. विवेकानंदन के प्रेरक भाषण से हुई, जिन्होंने छात्रों के अद्वितीय सहयोग की सराहना की, जिसने कोलोसस आई.एम.यू.एन. -वाय.पी. 2024 को एक शानदार सफलता बनाई।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.